बुधवार 10 दिसंबर 2025 ■ मूल्य 3.00 ■ वर्ष 03 ■ अंक 264 ■ पृष्ठ 08

गौतमबुद्ध नगर

JBT

www.thejbt.com

जनभावना टाइम्स

निष्पक्ष और निर्भीक खबर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, देहरादून, लखनऊ, अलीगढ़, मथुरा, हिसार, कैथल एवं करनाल से प्रकाशित

04 लोगों के अधिकारों की सुरक्षा... | 07 आईपीएल 2026 की नीलामी में 240 भारतीयों सहित 350 खिलाड़ी शामिल | 'वी शांताराम' में तमन्ना भाटिया की पहली... 08

कानून लोगों की सुविधा के लिए होने चाहिए असुविधा के लिए नहीं : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्राथमिकता लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि कानून या नियम आम लोगों की सुविधा के लिए होने चाहिए और उनकी वजह से किसी निर्दोष भारतीय को असुविधा नहीं होनी चाहिए।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि देश अब पूरी तरह 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' के दौर में है, जहां सुधार तेजी से और स्पष्ट मंशा के साथ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के सुधार सिर्फ अर्थव्यवस्था या राजस्व पर केंद्रित नहीं है, ये पूरी तरह से नागरिक-केंद्रित हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि सरकार का लक्ष्य लोगों की रोजमर्रा की परेशानियां दूर करना है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ सकें। बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को 'बहुत अच्छे दिशानिर्देश' दिए और यह संदेश दिया कि उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा मुद्दा 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' है।

इस बैठक में राजग के सभी सांसद शामिल हुए। रीजीजू ने कहा कि मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार की 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' चल पड़ी है और अब यह रुकेगी नहीं। यह सुधार देश के हर नागरिक की जिंदगी बदलने के लिए है। जब हम सुधार की बात करते हैं तो कुछ लोग इसे आर्थिक सुधार समझते हैं, कुछ राजनीतिक, कुछ प्रशासनिक या सांस्कृतिक सुधार। लेकिन 'सुधार' का असली मतलब है-हर नागरिक के जीवन में बेहतरी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस पर बल दिया कि जो भी कानून बनाया जाए, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जो किसी नागरिक के लिए नुकसानदेह हो या उसे परेशान करे। नियम और कानून आम लोगों के लिए बोझ नहीं होने चाहिए। सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियम-कानून जनता की सुविधा के लिए हों और उनकी जिंदगी बेहतर बनाएं। रीजीजू ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि नियम-कानून, व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए होने चाहिए, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं और कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो बिना किसी वजह लोगों के लिए परेशान खड़ी करे। उन्होंने कहा कि अब हम इसी दिशा में काम करेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और नगरपालिकाओं व पंचायतों जैसी स्थानीय स्वशासी संस्थाओं, सभी को इसी दिशा में काम करना चाहिए।

सूत्रों के मुताबिक, मोदी ने सांसदों से कहा कि वे आम लोगों की वास्तविक समस्याएं नियमित रूप से साझा करें, ताकि 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' हर घर तक पहुंच सके और लोगों की रोजमर्रा की परेशानियां दूर हो सकें। सूत्रों के अनुसार, मोदी ने यह भी कहा कि वह 30-40 पन्नों वाले फॉर्म और बेवजह की कागजी कार्रवाई की संस्कृति खत्म करना चाहते हैं।

माइक्रोसॉफ्ट एशिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश भारत में करेगा

नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सत्या नडेला ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। दोनों ने भारत में बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बारे में बात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सत्या नडेला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर भारत के 'एआई प्रथम भविष्य' को समर्थन देने के लिए 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये) के बड़े निवेश की घोषणा की। कंपनी का यह निवेश एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है। नडेला ने 'एक्स' पर लिखा कि भारत की तेजी से बढ़ती एआई संभावनाओं पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रेरणादायक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भारत की आकांक्षाओं को मजबूत करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एशिया में अब तक का अपना सबसे बड़ा निवेश—17.5 अरब डॉलर—भारत में कर रहा है, ताकि देश के एआई भविष्य के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और सॉवरेन क्षमताओं का विकास किया जा सके। नडेला ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत में एआई के अवसरों पर प्रेरणादायक बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, धन्यवाद। देश की महत्वाकांक्षाओं को सपोर्ट करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है - यह एशिया में हमारा अब तक का सबसे बड़ा निवेश है - ताकि भारत के एआई फर्स्ट भविष्य के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और सॉवरेन कैपेबिलिटीज बनाने में मदद मिल सके।" प्रधानमंत्री मोदी ने नडेला के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि जब एआई की बात आती है, तो दुनिया भारत को लेकर बहुत आशावादी है। सत्या नडेला के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। यह देखकर खुशी हुई कि भारत वह जगह है जहां माइक्रोसॉफ्ट एशिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश करेगा। भारत के युवा इस मौके का इस्तेमाल इनोवेशन करने और बेहतर दुनिया के लिए एआई की शक्ति का फायदा उठाने में करेंगे।

इंडिगो पर सरकार सख्त, उड़ानों में 10 फीसदी की कटौती

रिफंड, लगेज और यात्री सुविधा को लेकर सख्त आदेश

नई दिल्ली। इंडिगो संकट पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन को उड़ानों में 10 फीसदी की कटौती करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कंपनी को ये कहा गया है कि वो यात्रियों सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रिफंड और लगेज जल्द से जल्द वापस लौटाए।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने मंगलवार को 'एक्स' पोस्ट पर जारी एक बयान में कहा कि देशभर में बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल की अफरा-तफरी के बीच ऑपरेशन को स्थिर करने के लिए केंद्र ने इंडिगो के रूट्स में 10 फीसदी की कटौती की है। इससे पहले इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने राम मोहन नायडू से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पीटर एल्बर्स नागरिक उड्डयन मंत्री के सामने हाथ जोड़े नजर आए। राम मोहन नायडू ने आगे लिखा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को अपने कुल रूट्स में 10 फीसदी की कटौती करने का ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे एयरलाइन के ऑपरेशन्स को स्टेबल करने और आगे कैंसिलेशन कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते इंडिगो के क्रू-मेंबर रोस्टर, फ़्लाइट शेड्यूल और कम्युनिकेशन की कमी के कारण कई यात्रियों को बहुत परेशानी हुई। इसको लेकर जहां जांच और जरूरी कार्रवाई चल रही है, वहीं, एयरलाइन के टॉप मैनेजमेंट के साथ स्टेबिलाइजेशन उपायों का रिव्यू करने के लिए एक और बैठक हुई। मंत्री ने बताया कि इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को अपडेट देने के लिए मंत्रालय में बुलाया गया था। उन्होंने कन्फर्म किया कि 06 दिसंबर तक जिन फ़्लाइट्स पर असर पड़ा था, उनके 100 फीसदी रिफंड पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिगो को बिना किसी छूट के मंत्रालय के सभी निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें किराया तय करना और यात्रियों की सुविधा के उपाय शामिल हैं।

संक्षिप्त खबरें

रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस पर 57.47 करोड़ के बैंक फ्रॉड का मामला दर्ज

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल), इसके प्रमोटर्स/निदेशकों और अज्ञात बैंक अधिकारियों के खिलाफ 57.47 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया है। सीबीआई के मुताबिक, यह मामला बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरसीएफएल ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक कृत्यों के जरिए बैंक को 57.47 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 25 मार्च 2020 को आरसीएफएल का लोन अकाउंट एनपीए घोषित किया था और 4 अक्टूबर 2025 को इसे फ्रॉड घोषित किया। कंपनी 31 बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, एनबीएफसी और कॉर्पोरेट बॉन्डीज से कुल 9,280 करोड़ रुपये तक के लोन ले रही थी, जिनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी शामिल है। सीबीआई ने मुंबई के स्पेशल कोर्ट से तलाशी वारंट प्राप्त किए और 9 दिसंबर 2025 को आरसीएफएल के कार्यालय और निदेशक देवांग प्रवीन मोदी के पुणे स्थित आवासीय परिसर में तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान कई आपराधिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं और उन्हें जब्त किया जा रहा है।

लाल किला धमाका मामला:NIA ने जम्मू के जंगली इलाके में ली तलाशी

श्रीनगर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की एक टीम ने मंगलवा को दिल्ली में लाल किले के पास बीते 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट की जांच के तहत जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के जंगली इलाके में तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि एनआईए के अधिकारी पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से "व्हाइट कॉलर" टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए दो आरोपितों डॉ. अदील राथर और जसीर बिलाल वानी को साथ लेकर आए हैं। अधिकारियों के मुताबिक दोनों आरोपितों ने जांच करने वालों को दक्षिण कश्मीर जिले के मट्टन जंगल इलाके में कुछ ठिकानों के बारे में बताया था।

तकनीकी खराबी के कारण एमिरेट्स एयरलाइन की चेन्नई- दुबई फ्लाइट रद

चेन्नई। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की एमिरेट्स एयरलाइन की चेन्नई से दुबई जाने वाली उड़ान को मंगलवार तड़के तकनीकी खराबी के चलते रद्द करना पड़ा। उड़ान संख्या ईके-543, एयरबस ए-321 विमान से संचालित होने वाली थी और इसे सुबह 3:50 बजे उड़ान भरनी थी। एयरलाइन ने आधिकारिक बयान के अनुसार, विमान उड़ान भरने के लिए रनवे पर दौड़ना शुरू ही हुआ था कि पायलट ने तकनीकी समस्या महसूस की। पायलट ने तुरंत विमान को रनवे पर ही रोक दिया, जिससे संभावित बड़े हादसे को टाल लिया गया। इसके बाद कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी गई और विमान को टोइंग के जरिए पार्किंग बे में ले जाया गया। विमान में 284 यात्री और 12 क्रू मेंबर, कुल 296 लोग सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर बसों के माध्यम से शहर के विभिन्न होटलों में ठहराया गया। एयरपोर्ट तकनीकी टीम ने विमान की खराबी दूर करने का प्रयास किया, लेकिन समस्या जटिल होने के कारण उड़ान को स्थगित करना पड़ा।

नौ दिनों बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार

'बहुत खराब' से 'खराब' श्रेणी में पहुंची

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में नौ दिनों बाद मंगलवार को वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ तथा औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 अंक से नीचे 'खराब' श्रेणी में रहा।

हालांकि, यह राहत अल्पकालिक हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका है। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली द्वारा जारी किये गये छह-दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी तक गिरने की आशंका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार मंगलवार को अपराह्न चार बजे 24 घंटे का औसत एक्यूआई 282 रहा, जबकि सोमवार को इसी समय यह 314 और रविवार को 308 था। वैसे तो सीपीसीबी के 'समीर' ऐप ने निगरानी केंद्र वार प्रदूषण स्तर छह बजे तक नहीं जारी किया लेकिन 18 निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' (एक्यूआई 300 से ऊपर) और 20 पर 'खराब' (एक्यूआई 200 से ऊपर) दर्ज की गयी। राजधानी के प्रदूषण के बारे में ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) के कार्यक्रम प्रमुख मोहम्मद रफीउद्दीन ने कहा कि मंगलवार को तेज हवाओं के कारण दिल्ली का एक्यूआई पिछले कुछ दिनों के 300 से थोड़ा सुधरकर करीब 282 के आसपास पहुंच गया।

निर्वाचन आयोग नागरिकता के संबंध में शुरुआती चरण पर फैसला नहीं कर सकता: उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पूछा कि क्या निर्वाचन आयोग को किसी संदिग्ध नागरिक के मामले में जांच करने से रोका गया है और क्या ये जांच प्रक्रिया उसके संवैधानिक अधिकार से बाहर है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार सहित कई राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां कीं। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने संबंधित कानून और इस दलील का संज्ञान लिया कि आयोग नागरिकता के मुद्दे पर निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि उसका काम सिर्फ यह विचार करना होता है कि व्यक्ति भारतीय नागरिक है, उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तथा वह उसी निर्वाचन क्षेत्र में रहता है। यह भी दलील दी गई थी कि नागरिकता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि केवल केंद्र सरकार की ओर से गठित विदेशी न्यायाधिकरण ही इस संबंध में फैसला ले सकता है। न्यायाधीश ने पूछा कि आप कहते हैं कि निर्वाचन आयोग के पास किसी व्यक्ति को विदेशी या गैर-नागरिक घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन, वह मौजूदा दर्जे पर संदेह कर सकता है और मामले को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भेज सकता है। यह तथ्य कि वह (नागरिकता पर) संदेह कर सकता है, एक तरह से यह सुनिश्चित करता है कि उसके पास इस संबंध में निर्णय लेने की शक्ति है। क्या निर्वाचन आयोग नागरिकता के शुरुआती चरण पर निर्णय नहीं ले सकता? याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि एसआईआर प्रक्रिया क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण और प्रक्रियागत अनियमितताओं से ग्रसित है तथा इसमें नागरिकता साबित करने का भार असंवैधानिक रूप से आम मतदाताओं पर डाला गया है।

पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत, पीसी सेन और एसआईआर का विरोध करने वाले कई याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की विस्तृत दलीलें सुनीं। फरासत ने मतदाता सूचियों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक और वैधानिक ढांचे का जिक्र करते हुए कहा कि अनुच्छेद 324 से 329, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ मिलकर एक 'एकल संवैधानिक संहिता' बनाते हैं, जिसे अस्थायी संसद के रूप में कार्य करने वाली संविधान सभा की ओर से अधिनियमित किया गया था। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार के लिए केवल तीन शर्तों की पूर्ति आवश्यक है और वे हैं - भारतीय नागरिकता, 18 वर्ष की आयु तथा विशिष्ट अयोग्यताओं का अभाव।

फरासत ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरओपीए) इन आधारों को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन मतदाता सूची से बाहर करने के लिए नये आधार नहीं दे सकता। वरिष्ठ वकील ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मुझे मतदाता सूची में शामिल होने से रोकने या सूची से बाहर करने का कोई अधिकार नहीं है।

सूरत में एक ही दिन, एक साथ चार लोगों ने किया 20 अंगों का दान

सूरत। गुजरात के सूरत शहर में एक ही दिन, एक साथ चार व्यक्तियों के अंगदान की ऐतिहासिक घटना हुई। यह देश में शायद पहली ही बार है कि एक शहर में एक दिन इतने बड़े स्तर पर चार ब्रेनडेड घोषित व्यक्तियों के अंगदान हुए हों। इन चारों व्यक्तियों के कुल 20 अंगों का दान किया गया, जिससे अंगों की प्रतीक्षा में बैठे कई मरीजों को नया जीवन मिलेगा।

यह कार्य अंगदान जनजागृति चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रणेता दिलीप दादा देशमुख के जन्मदिन पर किया गया। दिलीपदादा देशमुख लंबे समय से समाज में अंगदान के जनजागरण के लिए कार्यरत हैं। अंगदान जनजागृति चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रणेता दिलीप देशमुख ने हिन्दुस्थान समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि चार ब्रेनडेड घोषित व्यक्तियों के कुल 20 अंगों से अनेक मरीजों को नया जीवन मिलेगा। यह सूरत के लिए ही नहीं बल्कि देश के अंगदान के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि पिछले 6 वर्षों से मैं अंगदान के कार्यक्रम को आयोजित कर रहा हूँ। मैं खुद लिवर फेलियर से पीड़ित होकर ट्रांसप्लांट करा चुका हूँ और अब अंगदान के लिए जन जागरूकता फैलाने में लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि रक्तदान की तरह अंगदान के प्रति भी लोग जागरूक हों और अंगदान करने की तरफ आगे बढ़ें।

नर्सिंग काउंसिल के उपाध्यक्ष इक़बाल कड़ीवाला ने कहा कि हमारा प्रयास है कि लोग स्वेच्छा से अंगदान के प्रति जागरूक बनें और अंगदान जनजागृति अभियान एक जनांदोलन बने। अंगदान जैसे कार्य के साथ एक ही दिन चार सफल अंगदान होना दिलीपदादा देशमुख के जन्मदिन को वास्तव में सार्थक और प्रेरणादायक बना दिया है।

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले टी-20 में धूल चटाई, 101 रन से हराया

कटक। भारत ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका को मंगलवार को यहां 101 रन के बड़े अंतर से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

भारत ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर छह विकेट पर 175 रन बनाने के बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी को 12.3 ओवर में 74 रन पर समेट दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने सबसे ज्यादा 22 रन बनाये।

भारत के लिए अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिये।

मुख्यमंत्री ने भलस्वा और जहांगीरपुरी में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का किया निरीक्षण

गरीब परिवारों का सपना दिल्ली सरकार पूरा करेगी : रेखा गुप्ता

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने गरीबों के हित में कार्य नहीं किया। लेकिन, वर्तमान की भाजपा सरकार दिल्ली में रहने वाले गरीबों के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने गरीबों से सिर्फ वादे किए, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। मौजूदा भाजपा सरकार यह पक्का करने के लिए काम कर रही है कि गरीब परिवारों के पास रहने के लिए सही घर हों। रेखा गुप्ता ने मंगलवार को भलस्वा में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का निरीक्षण किया। अधिकारियों को इस कैंपस में पार्किंग, मार्केट और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यहां ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी तथा बच्चों व बुजुर्गों के लिए सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि ये फ्लैट्स भले ही सालों पहले तैयार हो गए थे, लेकिन पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण खाली ही रह गए और अब जर्जर स्थिति में हैं। हमारी सरकार झुग्गियों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का मकान देने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इस कड़ी में आज इन ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का निरीक्षण कर यहां की स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने कहा कि हमने जो प्लान बनाया है, उसमें फ्लैट को पूरी तरह से मॉडल बनाकर हर प्रकार की सुविधा होगी। दिल्ली की सरकार गरीबों के हित में कार्य करने वाली सरकार है। हम जो प्लान बनाकर लाए हैं, उसे इसी कार्यकाल में पूरा कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ भलस्वा स्थित ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का निरीक्षण किया। वर्षों पूर्व निर्मित ये फ्लैट्स पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण उपयोग में नहीं आ सके और अब जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं। अब हमारी सरकार इन परिसरों को पूरी तरह विकसित कर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आज विस्तृत आकलन कर अधिकारियों को पार्किंग, मार्केट जोन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन, प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी, तथा बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक सामुदायिक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए गए। ताकि झुग्गीवासी यहां बेहतर, सुरक्षित और सम्मानपूर्वक रह सकें।

नेहरू पार्क में बनेगा भव्य स्कल्प्चर पार्कः

एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल का निरीक्षण

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने परिषद अध्यक्ष केशव चंद्रा के साथ नेहरू पार्क में प्रस्तावित स्कल्प्चर पार्क के लिए चयनित स्थान का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "विकसित भारत @2047" विज़न और कला–संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पद्मश्री कलाकार अद्वैत गडनायक, वरिष्ठ कलाकार टूटू पटनायक और एनडीएमसी अधिकारी भी मौजूद रहे।

चहल ने बताया कि स्कल्प्चर पार्क के लिए अंतिम स्थान तय करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी। स्थान चयन के बाद एनडीएमसी एक भव्य सिम्पोज़ियम आयोजित करेगा, जिसमें देशभर के लगभग 15 प्रसिद्ध मूर्तिकार–जिनमें पद्म और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कलाकार भी शामिल होंगे–एक महीने तक लाइव स्कल्प्चर तैयार करेंगे। हर मूर्ति 10 से 15 फीट ऊँची होगी और इन्हें नेहरू पार्क स्थित नए विकसित स्कल्प्चर पार्क क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि एनडीएमसी ने कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मई 2025 में आर्ट एंड कल्चर विभाग बनाया है। इस वर्ष कला-संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 40 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जो एनडीएमसी के कुल खर्च का लगभग 1% है। इसके साथ एक अर्बन आर्ट्स एंड कल्चर फोरम भी गठित किया गया है, जो विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों और परियोजनाओं को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएगा।

चहल के अनुसार, यह पहल एनडीएमसी क्षेत्र को एक जीवंत, आकर्षक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जिला बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे न केवल कलाकारों को मंच मिलेगा बल्कि पर्यटन को भी मजबूती मिलेगी, जिससे विकसित भारत 2047 के विज़न को गति प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि भारत अपनी कला, संस्कृति और रचनात्मकताको वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करे। प्रस्तावित स्कल्प्चर पार्क इसी विज़न का प्रतीक होगा, जहाँ आधुनिक सोच, सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक ऊर्जा एक साथ दिखाई देंगी।

संक्षिप्त खबरें

डीटीसी चालक की हत्या में पिता-पुत्र समेत 3 गिरफ्तार

नई दिल्ली। अमन विहार इलाके में शनिवार देर रात रोडरेज के दौरान डीटीसी चालक विकास की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच ने पिता-पुत्र समेत तीन आरोपियों को दबोच लिया। अमन विहार थाना पुलिस इस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। डीसीपी आदित्य गौतम के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों की पहचान 50 वर्षीय राजू, उसके बेटे हर्ष और भतीजे रोशन के रूप में हुई है। राजू मुंडका निवासी है और एमसीडी में कार्यरत है। शनिवार की रात रोशन के भाई की बारात अमन विहार के एक बैंक्वेट हॉल में आई थी। राजू वहीं पत्नी के साथ कार से पहुंचा था। उसी समय सड़क पर भीड़ के चलते जाम लग गया। पीछे से आ रही डीटीसी बस फंस गई। बस चालक विकास और परिचालक उमेश ने राजू से कार एक ओर करने को कहा। इसी बात पर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला जानलेवा हमले में बदल गया। राजू ने फोन कर अपने बेटे हर्ष, भतीजे रोशन और साथी राहुल को बुलाया था। चारों ने विकास और उमेश की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट रोकने आया एक राहगीर भी घायल हो गया। तीनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 27 वर्षीय विकास ने दम तोड़ दिया।

छात्र की हत्या के मामले में दो नाबालिग समेत 4 पकड़े

नई दिल्ली। सराय रोहिल्ला इलाके में मोबाइल लूट का विरोध करने पर 12वीं के छात्र आर्यन की चाकू घोंपकर हत्या करने वाले दो नाबालिगों समेत चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने 30 सितंबर की रात प्रताप बाग निवासी आर्यन पर हमला किया था। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल चाकू, घटना के समय पहने कपड़े और चोरी की स्कूटी बरामद की है। डीसीपी राजा बांठिया के अनुसार, बंदर वाला बाग के पास युवक गंभीर रूप से घायल मिला था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला हत्या में दर्ज कर जांच शुरू की। प्रताप बाग निवासी आर्यन 12वीं कक्षा का छात्र था और हत्या वाली रात गुलाबी बाग में एक शादी में जा रहा था। जांच के दौरान हेडकांस्टेबल संदीप कुमार ने फुटेज की जांच की, जिसमें चार युवक घटनास्थल से भागते दिखाई दिए।

रुपयों के विवाद को लेकर हुई कहासुनी में कर दी युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ, एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड और थाना गीजपुर की संयुक्त टीम ने हत्या के मामले का खुलास करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और 100 से ज्यादा सीडीआर खंगालकर आरोपित तक पहुंच बनाई। पकड़े आरोपित की पहचान कलीम (32) के रूप में हुई है। पुलिस ने इसे जामा मस्जिद इलाके से पकड़ा है। आरोपित ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि उसने पैसों के विवाद के चलते दलिप की हत्या की थी। वारदात में प्रयुक्त पत्थर का टुकड़ा बरामद किया गया है।

पूर्वीजिले के पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने मंगलवार को बताया कि आठ दिसंबर की सुबह करीब 11 बजे थाना गाजीपुर को सूचना मिली कि पेपर मार्केट के पास, कचरा फेंकने की जगह के पास एक शव पड़ा है। पुलिस और क्राइम टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मृतक के चेहरे पर गंभीर चोटें थीं। जिससे साफ था कि उसकी निर्ममता से हत्या की गई है। जांच में मृतक की पहचान खोड़ा कॉलोनी निवासी दलिप (45) के रूप में हुई। हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए संयुक्त टीम बनाकर मृतक की अंतिम गतिविधियों को ट्रेस करने के लिए इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। तकनीकी निगरानी के दौरान पता चला कि मृतक के संपर्क में आया व्यक्ति कलीम है, जो वारदात के बाद खोड़ा से फरार होकर गुरुग्राम के बदशाहपुर और पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में घूम रहा था। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि लगातार निगरानी रखते हुए पुलिस ने कलीम को जामा मस्जिद से पकड़ लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उस पर दलिप पैसे लौटाने का दबाव बना रहा था। इसी विवाद के चलते उसने गुस्से में आकर दलिप पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

एनईपी 2020 और प्रस्तावित एचईसीआई बिल के खिलाफ केवाईएस की जोरदार रैली

जंतर-मंतर पर उठी मुफ्त एवं समान शिक्षा की मांग

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) बिल 2025 के विरोध में क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) ने ज्वाइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन (जेएएफएमई) द्वारा आयोजित जंतर-मंतर रैली और संसद मार्च में सक्रिय भागीदारी निभाई। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट रूप से मांग रखी कि एनईपी 2020 और एचईसीआई बिल को तुरंत रद्द किया जाए तथा देश के सभी विद्यार्थियों को केजी से पीजी तक मुफ्त और समान सार्वजनिक वित्त-पोषित शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।

केवाईएस ने आरोप लगाया कि एनईपी 2020 ने देश की शिक्षा प्रणाली को बदतर कर दिया है और दोहरी शिक्षा व्यवस्था (निजी तथा सरकारी विद्यालयों) के माध्यम से सामाजिक गैरबराबरी को और मजबूत किया है। संगठन के अनुसार, नीति के चलते व्यवसायिक और अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे गरीब और हाशिये पर रहने वाले छात्रों को औपचारिक शिक्षा से दूर करके असंगठित श्रम बाजार की ओर धकेला जा रहा है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में प्रदर्शनकारियों ने शुल्क वृद्धि, सीटों में कटौती, फंड में भारी कमी तथा 'मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा' प्रणाली को बढ़ावा देने जैसी नीतियों को जनविरोधी बताया। विरोधकर्ताओं ने कहा कि इन कदमों ने लाखों छात्रों को गुणवत्तापूर्ण एवं औपचारिक उच्च शिक्षा प्रणाली से बाहर कर दिया है। रैली में यह भी रेखांकित किया गया कि एनईपी लागू होने के बाद कई राज्यों में हजारों स्कूल बंद किए जा चुके हैं और सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों को क्रमबद्ध रूप से फंड से वंचित किया जा रहा है, जिससे कॉर्पोरेट हितों को लाभ पहुँचाया जा सके।

केवाईएस ने कहा कि यह स्थिति बेहद शर्मनाक है कि सरकार हाशिये के समुदायों के छात्रों के लिए अनौपचारिक शिक्षा संस्थानों को ही उपयुक्त विकल्प मान रही है, जबकि यह संस्थान बुनियादी सुविधाएँ तक उपलब्ध नहीं करा पाते। प्रस्तावित एचईसीआई बिल 2025 को लेकर भी गंभीर चिंताएँ व्यक्त की गईं।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 2018 के मसौदे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांत इस बिल की दिशा को स्पष्ट करते हैं–जिसमें सार्वजनिक वित्त-पोषण को कम करना, शिक्षा का केंद्रीकरण, और उच्च शिक्षण संस्थानों को कुछ चुनिंदा समूहों के हित में ढालने जैसे प्रावधान शामिल हैं। यूजीसी की निधि आवंटन भूमिका हटाकर इसे उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी को सौंपा जाना भी इसी दिशा का संकेत है, जो संस्थानों को अनुदान के बजाय ऋण उपलब्ध कराती है।

केवाईएस ने कहा कि इन नीतियों के माध्यम से वंचित छात्रों का शिक्षा अधिकार छीना जा रहा है और ऑनलाइन व मिश्रित शिक्षा मॉडल थोपकर उन्हें औपचारिक शिक्षा से दूर किया जा रहा है। संगठन ने एनईपी 2020 और एचईसीआई बिल को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए घोषणा की कि आने वाले समय में केंद्र सरकार की भेदभावपूर्ण शिक्षा नीतियों के खिलाफ आंदोलन और तेज किया जाएगा।

पुलिस कमिश्नरों को भेजे गए धमकी भरे ईमेल का खुलासा, युवक गिरफ्तार

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े साइबर धमकी मामले का पर्दाफाश करते हुए 22 वर्षीय अभय को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने दिल्ली और बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नरों को फर्जी नाम से आतंकवादी संगठन के तौर पर धमकीभरे ईमेल भेजे थे। मामला सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और पूरे मामले की गहराई से जांच की गई।

क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरान ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि सात दिसंबर को पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के आधिकारिक ईमेल पर एक धमकीभरा मेल मिला। मेल में खुद को प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा बताया गया था और पैसे की मांग की गई थी। मेल में एक संदिग्ध ईमेल आईडी को सीसी भी किया गया था। जिससे शक और बढ़ गया। तुरंत जांच शुरू हुई। तकनीकी जांच में एक मोबाइल नंबर सामने आया। टीम ने गुरुग्राम सेक्टर-37 से मोहित नाम के युवक को पकड़ा।

पूछताछ में उसने बताया कि वह कई दिनों से किसी अनजान व्यक्ति की ऑनलाइन हरकतों से परेशान था। उसे अंतरराष्ट्रीय स्पैम कॉल आ रही थीं और फर्जी क्यूआर कोड भेजे जा रहे थे।जांच के दौरान मोहित ने एक लड़की के साथ अपनी पिछली बातचीत के बारे में बताया और कुछ समय बाद उसे अभय नाम के एक व्यक्ति का फोन आया। जिसने खुद को उसका प्रेमी बताया और उसे उससे दूर रहने को कहा। इस लीड पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दिल्ली के साकेत, सैदुलजाब के रहने वाले अभय शी (22) का पता लगाया और उसे गिरफ्तार किया।

लगातार पूछताछ के दौरान अभय शी ने कबूल किया कि मोहित के साथ निजी विवाद के कारण, उसने उसके खिलाफ एक ऑनलाइन उत्पीड़न अभियान चलाया था। उसने मोहित की पहचान से मिलते-जुलते कई फर्जी ई-मेल आईडी बनाने, अपने डिजिटल फुटप्रिंट छिपाने के लिए स्पूफिंग टूल्स और वीपीएन सेवाओं का इस्तेमाल करने, और सीपी दिल्ली और बेंगलुरु के ऑफिशियल ई-मेल पर धमकी भरे ई-मेल भेजने की बात कबूल की। इसी तरह का धमकी भरा मैसेज पीसीआर गंगा नगर, राजस्थान पुलिस को मोबाइल पर एक वर्चुअल इंटरनेशनल नंबर से भेजा गया था। जिसमें कथित भेजने वाले ने फिर से एक इंटरनेशनल बैन संगठन से अपने लिंक का दावा किया और एजेंसी को अपने जासूसों को रिहा करने के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की, नहीं तो कारों में धमाके कर दिए जाएंगे जैसी बातें लिखी। मोहित की निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल करके कई फर्जी साइबर शिकायतें दर्ज की गईं। उसने बताया कि उसने ये सभी काम अपने पर्सनल मोबाइल फोन से किए, जिसे बरामद कर लिया गया है।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि आरोपित के मोबाइल में कई जरूरी डिजिटल सबूत मिले हैं। कुछ डाटा डिलीट किया गया है, जिसे रिकवर करने का काम चल रहा है। पुलिस ने आरोपित से एक मोबाइल फोन बरामद किया है। इसी फोन से फर्जी ईमेल बनाए गए थे और धमकी भरे मेल भेजे गए थे। वहीं जांच में पता चला कि अभय शी मूल रूप से जमशेदपुर का रहने वाला है। वह बीसीए का छात्र है और फ्रीलांस वेब डेवलपर के रूप में काम करता था।

इग्नू के सभी 70 केंद्रों पर स्थापित होंगे स्किल सेंटर

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत पूरे देश में स्किल ट्रेनिंग को मजबूत करने के लिए 9 दिसंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन किया। नई दिल्ली के कौशल भवन में इग्नू की वाइस चांसलर प्रो. उमा कांजीलाल और मंत्रालय की सेक्रेटरी देबाश्री मुखर्जी की मौजूदगी में हुए इस समझौते के तहत इग्नू के सभी 70 रीजनल सेंटर्स में स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये सेंटर एनएसक्यूएफ-अनुरूप और इंडस्ट्री-फोकस्ड ट्रेनिंग प्रदान करेंगे। इग्नू अपने विशाल नेटवर्क और डिजिटल लर्निंग सिस्टम की मदद से पीएमकेवीवाई 4.0 के लिए आधिकारिक ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में काम करेगा। एमओयू के तहत ट्रेनर्स की ट्रेनिंग, इंडस्ट्री पार्टनरशिप, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। यह पहल महिलाओं, ग्रामीण युवाओं, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों और पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए नए अवसर खोलेगी तथा स्थानीय रोजगार इकोसिस्टम को मजबूत करेगी।

हर्ष फायरिंग करने वाला वांछित आरोपी गिरफ्तार, अवैध पिस्टल बरामद

नोएडा। नोएडा के थाना फेज-2 पुलिस ने हर्ष फायरिंग के एक वायरल वीडियो में चिन्हित किए गए वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान पंकज तंवर पुत्र सतबीर तंवर, निवासी ग्राम मांडी, थाना फतेहपुर बेरी, दिल्ली, उम्र लगभग 29 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे सिटी पार्क, सेक्टर-93, नोएडा से गिरफ्तार किया। आरोपी से एक अवैध पिस्टल 32 बोर, एक जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार, 6 दिसंबर को सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आरोपी को अवैध हथियार से फायरिंग करते हुए देखा गया था।

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी की तलाश में विशेष टीम गठित की गई। लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी सेक्टर-93 के पास दिखाई दिया है। सूचना मिलते ही टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे मौके से दबोच लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के कब्जे से वही अवैध पिस्टल बरामद की गई, जिसका उपयोग उसने वायरल वीडियो में हर्ष फायरिंग के दौरान किया था। पुलिस ने हथियार, जिंदा कारतूस और मैगजीन को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।

थाना फेज-2 में आरोपी के खिलाफ अन्य धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि हर्ष फायरिंग न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह जान माल के लिए गंभीर खतरा भी पैदा करता है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करने से पहले सौ बार सोचे।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हर्ष फायरिंग से जुड़े मामलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी से पूछताछ जारी है ताकि हथियार की सप्लाई और किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में उसकी संलिप्तता के बारे में जानकारी हासिल की जा सके।

कॉल सेंटर ठगी का भंडाफोड़, बेरोजगार युवाओं से पैसे ठगने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार

नोएडा। भारत देश की मल्टी नेशनल कंपनियों में नौकरी दिलवाने के नाम पर बेरोजगार युवक-युवतियों से ठगी करने वाले एक कॉल सेंटर का थाना साइबर क्राइम व थाना फेस-1 पुलिस ने संयुक्त रूप भंडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 1 लैपटॉप, 3 चैकबुक, 3 पासबुक, 19 डेबिट कार्ड, 29 सिम कार्ड, 30 मोबाइल फोन व 172 वर्क कालिंग संबंधित डाटा बरामद किया है।

डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि आज थाना साइबर क्राइम व थाना फेस-1 पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए लोकल इंटेलिजेंस व बीट पुलिसिंग की सहायता से देश की मल्टी नेशनल कंपनियों में नौकरी दिलवाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड साइबर अपराधी विशाल कुमार पुत्र उमेश कुमार को सेक्टर-2 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि यह गिरोह फर्जी मेल आईडी, कॉल लेटर एंव अपॉइंटमेंट बॉन्ड जैसे दस्तावेजों का उपयोग करते हुए लोगों से कमीशन के नाम पैसे लेता था।

डीसीपी ने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया है कि कॉल सेन्टर के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को काल करके उनको मल्टिनेशल कम्पनी में नौकरी दिलाने का लालच देकर रजिस्ट्रेशन के नाम पर 4 हजार से 25 हजार रूपये की ठगी की जाती थी। विभिन्न कम्पनियों के नाम पर फर्जी ईमेल आईडी तैयार कर लोगों को ऑफर लेटर भेजकर उनसे प्लेसमेन्ट के नाम पर विभिन्न फर्जी बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर कराते थे। अभियुक्त, द्वारा करीब 10 से अधिक फर्जी बैक खातों में बेरोजगार युवकों से लेनदेन करते थे। उन्होंने बताया कि सभी खातों को पुलिस द्वारा फ्रीज कराया गया है।

बार-रेस्टोरेंट की सघन चेकिंग जारी, नव वर्ष से पहले सुरक्षा इंतजामों पर प्रशासन सख्त

नोएडा। गोवा के नाइट क्लब में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद गौतमबुद्धनगर प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है। जन-सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की ओर से जिलेभर में बार, रेस्टोरेंट और विभिन्न मनोरंजन स्थलों की संयुक्त सघन जांच जारी है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में चल रहे इस अभियान में मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ), फायर सर्विस विभाग, आबकारी विभाग और विद्युत सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीमें शामिल हैं, जो सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच कर रही हैं। अधिकारियों के अनुसार, इस चेकिंग अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले के किसी भी बार या मनोरंजन स्थल में अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा या जन-सुरक्षा नियमों की अनदेखी न होने पाए। गोवा जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन ने सभी संवेदनशील स्थानों पर औचक निरीक्षण तेज कर दिया है। अब तक लगभग 50 बार और रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया जा चुका है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की गहन जांच की गई। चेकिंग के दौरान टीमों द्वारा आपातकालीन निकास द्वारों की उपलब्धता और उनकी कार्यशीलता, फायर अलार्म, फायर एक्सटिंगिग्विशर जैसे उपकरणों की वैधता और स्थिति, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, अर्थिंग और ओवरलोडिंग की संभावनाओं की गहन जांच की जा रही है। साथ ही गैस सिलिंडरों की सुरक्षित स्थिति, वेंटिलेशन और स्मोक मैनेजमेंट, निर्धारित क्षमता के अनुरूप भीड़ नियंत्रण और लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन भी प्रमुख रूप से किया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार, अधिकांश प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानक संतोषजनक पाए गए हैं, वहीं कुछ स्थानों पर कमियां मिली हैं जिन पर तत्काल सुधार के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि गंभीर अनियमितताओं की स्थिति में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगामी नववर्ष समारोह को देखते हुए प्रशासन ने चेकिंग को और अधिक प्रभावी और तेज करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भीड़भाड़ के बीच किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। पुलिस कमिश्नरेट ने सभी बार और रेस्टोरेंट संचालकों से अपील की है कि वे अग्नि, विद्युत और जन-सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन करें। साथ ही आम नागरिकों से भी आग्रह किया गया है कि यदि उन्हें किसी मनोरंजन स्थल पर सुरक्षा संबंधी कमी नजर आए, तो संबंधित विभाग को तुरंत जानकारी दें, जिससे समय पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

मर्सिडीज कार के लिए कंपनी ने 27.50 लाख रुपये में खरीदा 0001 नंबर

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर के एक निजी प्रतिष्ठान ने मर्सिडीज कार के लिए '0001' वीआईपी वाहन नंबर 27.50 लाख रुपये की रिकॉर्ड बोली लगाकर खरीदा है। परिवहन विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में किसी आकर्षक नंबर के लिए पहली बार वाहन मालिक की ओर से इतनी बड़ी राशि जमा कराई गई है। कंपनी ने बोली जीतने के बाद पूरी रकम जमा भी करा दी है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 'यूपी-16 एफएच' श्रृंखला के आकर्षक नंबरों की ऑनलाइन नीलामी में यह नंबर दवा कंपनी 'एम/एस अविओरियन प्राइवेट लिमिटेड' ने हासिल किया। विभाग के मुताबिक, '0001' नंबर का 'बेस प्राइस' एक लाख रुपये है, जिसके आधार पर नीलामी शुरू होती है। विभाग ने बताया कि कंपनी ने 27,50,000 रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाई और नंबर अपने नाम सुरक्षित कर लिया।

गौतमबुद्ध नगर के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) नंद कुमार ने बताया कि आकर्षक नंबरों के लिए लोगों में हमेशा विशेष उत्साह रहता है और कई वाहन मालिक इन्हें पाने के लिए ऊंची बोली लगाने में भी पीछे नहीं रहते। इस बार बोली न सिर्फ सर्वाधिक रही, बल्कि पूरे पैसे जमा भी करा दिए गए।

क्षत्रिय करणी सेना ने किया संजय निषाद के आपत्तिजनक बयान के खिलाफ प्रदर्शन

नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री (मत्स्य विभाग) डॉ. संजय निषाद द्वारा बलिया जनपद और देशवासियों के प्रति दिए गए आपत्तिजनक और अमर्यादित बयान के विरोध में क्षत्रिय करणी सेना ने ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के सूरजपुर स्थित जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सेना के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम वेद प्रकाश पांडे को सौंपा।

जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन के दौरान क्षत्रिय करणी सेना के नोएडा महानगर अध्यक्ष ठाकुर संग्राम सिंह चौहान ने कहा कि मंत्री संजय निषाद की टिप्पणी से क्षत्रिय समाज, बलिया निवासी और स्थानीय नागरिकों में गहरा रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि बलिया एक गौरवशाली और ऐतिहासिक जनपद है, जिसने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक अमर शहीद मंगल पांडे जैसे वीरों को जन्म दिया है। ऐसे सम्मानित जनपद के लिए असंवेदनशील टिप्पणी कतई स्वीकार्य नहीं है।

उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक जिम्मेदार पद पर बैठे मंत्री से संयमित भाषा की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान न केवल संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी बिगाड़ते हैं।

एसडीएम को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि मंत्री के विवादित बयान की न्यायिक जांच कराई जाए। सामाजिक भावनाओं को आहत करने के चलते उन्हें तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। संवैधानिक मर्यादा भंग करने पर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई हो।

वहीं ज्ञापन में क्षत्रिय करणी सेना ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय के भीतर संजय निषाद को निलंबित नहीं किया गया और उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। संगठन ने स्पष्ट किया कि इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन के दौरान प्रदेश प्रवक्ता विपिन सिंह सूर्यवंशी, नोएडा महानगर अध्यक्ष ठाकुर संग्राम सिंह चौहान, जोगिंदर, शैलेंद्र, निक्कू राजा, सूरज, शिवम, सोनू, मोहित, आकाश सहित अन्य लोग उपस्थित रहें।

सोसाइटी में घरेलू सहायिका ने छठी मंजिल से कूदकर जान दी

नोएडा। नोएडा की एक रिहायशी सोसाइटी में मंगलवार सुबह एक घरेलू सहायिका ने छठी मंजिल से कूदकर कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, घटना सेक्टर-79 स्थित एक सोसाइटी की है। उन्होंने बताया कि सोरखा गांव की निवासी घरेलू सहायिका कल्पना पाल (25) ने छठी मंजिल पर स्थित उस व्यक्ति के फ्लैट की बालकनी से छलांग लगा दी जिसके यहां वह काम करती थी। उन्होंने बताया कि आत्महत्या के कारणों का पता अभी नहीं चल सका है। पाल के परिजनों को सूचना दे दी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच के लिए सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रगति पर मेरठ मंडल के विशेष रोल प्रेक्षक की समीक्षा

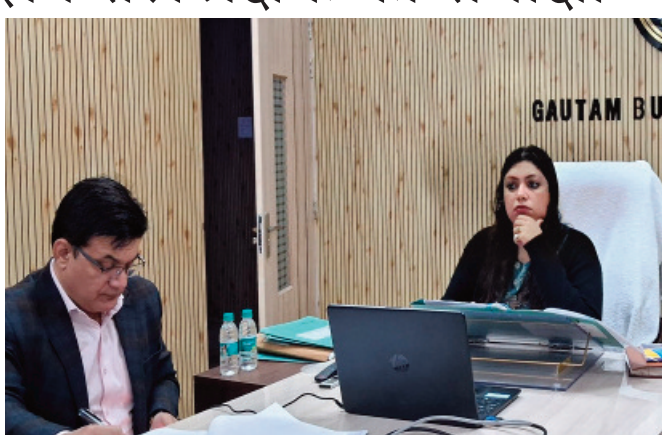

गौतमबुद्धनगर। मतदाता सूची को अद्यतन और शुद्ध बनाने के उद्देश्य से चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति की सोमवार को समीक्षा की गई। समीक्षा मीटिंग की अध्यक्षता मेरठ मंडल के विशेष रोल प्रेक्षक एवं संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निखिल गजराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने बैठक में अब तक पूरी की गई गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन और मैपिंग पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रपत्र-06 एवं प्रपत्र-08 से संबंधित आवेदनों की स्थिति, लंबित प्रकरणों के निस्तारण और SIR से जुड़े कार्यों की अद्यतन प्रगति भी प्रेक्षक के समक्ष रखी गई। उन्होंने कहा कि समस्त प्रक्रियाओं की नियमित निगरानी की जा रही है, जिससे कार्य निर्धारित समयसीमा में और बिना त्रुटि के पूरे हो सकें। विशेष रोल प्रेक्षक निखिल गजराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता हो। उन्होंने यह भी कहा कि पुनरीक्षण केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती का महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए प्रत्येक प्रविष्टि तथ्यों की पुष्टि के साथ दर्ज की जाए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

दीक्षांत समारोह के अंतिम दिन 2500 छात्रों को डिग्री मिली

नोएडा। एमिटी विश्वविद्यालय में चल रहे चार दिवसीय दीक्षांत समारोह के अंतिम दिन आज 2500 से अधिक छात्रों को उपाधियाँ प्रदान की गईं। इस अवसर पर एमिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स और एमिटी स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की चेयरपरसन श्रीमती दिव्या चौहान तथा विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. बलविंदर शुक्ला ने विभिन्न संस्थानों के छात्रों को डिग्रियाँ सौंपीं। समारोह में एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड एलाइड साइंसेस के 358, एमिटी स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस के 183, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के 126, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेस के 67, एमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के 40, एमिटी स्कूल ऑफ डिजाइन के 178, एमिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के 167, एमिटी स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के 211 तथा एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के 142 सहित अन्य संकायों के विद्यार्थियों को उपाधियाँ दी गईं। श्रीमती दिव्या चौहान ने छात्रों को सफलता की बधाई देते हुए उन्हें अभिभावकों और शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ रहने तथा ज्ञान, नवाचार और नैतिकता के साथ समाज और देश के विकास में योगदान देने की प्रेरणा दी। वहीं, कुलपति डॉ. बलविंदर शुक्ला ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी विद्यार्थी अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

कंपनी में कामकाज के दौरान मैनेजर की मौत

नोएडा। नोएडा की एक गारमेंट्स बनाने की कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत शख्स कामकाज के दौरान मूर्छित हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना सेक्टर-63 के प्रभारी निरीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि सेक्टर-26 में रहने वाले संजय प्रसाद सेक्टर-63 स्थित एक गारमेंट्स बनाने की कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करते थे। रात को वह कंपनी में काम कर रहे थे, तभी वह मूर्छित होकर हो गए। उनके साथ काम करने वाले लोगों ने गंभीर हालत मे उनको नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अस्पताल की सूचना पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बोलेरो पिकअप चालक ने महिला को मारी टक्कर, मौत

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के थाना ईकोटेक-3 के प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने बताया कि संजय सिंह तोमर पुत्र जगदीश सिंह तोमर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी पत्नी बन्ना तोमर उम्र 38 वर्ष अपने घर से ड्यूटी पर जा रही थी, तभी एक बोलेरो मैक्स के चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दिया। उन्होंने बताया कि इस घटना में महिला की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अपना घर आश्रय में महिला की संदिग्ध मौत

नोएडा के थाना सेक्टर-24 क्षेत्र के सेक्टर-34 स्थित अपना घर आश्रय में रहने वाली एक 85 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। संस्था की कर्मचारी नीलम ने उसने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। थाना प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार ने बताया कि मृतका का नाम शांति देवी है। उन्होंने बताया की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवा रही है।

मानसिक तनाव में युवक ने खाया जहर

थाना सेक्टर-20 के प्रभारी निरीक्षक डीपी शुक्ल ने बताया कि निक्कू कुमार निवासी निठारी गांव उम्र 24 वर्ष ने अपने घर पर मानसिक तनाव के चलते कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहां से उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया है। उन्हें बताया कि अस्पताल की सूचना पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शेयर बाजार में निवेश के नाम पर इंजीनियर से 50 लाख रुपये ठगे

नोएडा। साइबर अपराधियों ने इंजीनियर को शेयर बाजार में निवेश करने का झांसा देकर 50 लाख रुपये ठग लिए। जालसाजों ने पीड़ित को 20 से 30 प्रतिशत मुनाफा होने का विश्वास दिलाया। पीड़ित ने साइबर अपराध थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित उपवन सोसाइटी में रहने वाले राजेंद्र डोगरा गुजरात की प्राइवेट कंपनी के कार्यालय में कार्यरत हैं।

वर्तमान में वह घर से कार्य कर रहे हैं। वह शेयर बाजार में निवेश करने में भी रुचि रखते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 20 सितंबर को प्रवीण पटेल नाम के व्यक्ति ने फोन कॉल कर खुद को शेयर बाजार का विशेषज्ञ होने का दावा किया। उसने कहा कि वह अमेरिका से लौटा है। उसने राजेंद्र को एक व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़कर शेयर बाजार का प्रशिक्षण देना शुरू किया। राजेंद्र से सेबी पंजीकृत टेनकोर नाम से एक ऐप मोबाइल में डाउनलोड कराकर पंजीकरण कराया। उसने शुरुआत में 50 हजार रुपये का निवेश कराया। आरोपी ने दो दिन बाद नौ हजार रुपये खाते में मुनाफा भेजकर राजेंद्र का विश्वास जीत लिया। विश्वास होने पर राजेंद्र ठगों के कहने पर रकम भेजते रहे।

उन्होंने चार से 23 अक्तूबर तक कई बार में 50 लाख पांच हजार रुपये निवेश कर दिए। मुनाफे समेत रकम निकालने का प्रयास करने पर ठगों ने 15 प्रतिशत कर के रूप में और रकम जमा करने के लिए कहा। रकम नहीं देने पर ठगों ने संपर्क तोड़ लिया। पीड़ित ने एनसीआरपी और साइबर अपराध थाने में शिकायत की। साइबर सेल की एडीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ठगी में संलिप्त बैंक खातों की जानकारी जुटाने संग रकम को फ्रीज कराने की प्रक्रिया चल रही है। ठगों की तलाश में पुलिस टीम लगी हैं।

दो सगे भाइयों पर मारपीट करने का आरोप

दादरी। बील अकबरपुर गांव में रहने वाले युवक ने पड़ोस में रहने वाले दो सगे भाइयों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित के सिर में गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने आरोपी भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सरोज कुमार झा बील अकबरपुर गांव में परिवार के साथ रहते हैं। सरोज कुमार ने पुलिस को बताया कि सोमवार को वह अपनी ड्यूटी से घर पहुंचे थे। वह घर के बाहर अपनी कार खड़ी कर रहे थे। इसी बीच पड़ोसी सगे भाई कृष्णा और अर्जुन ने गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोपी भाइयों ने पीड़ित को बुरी तरह पीटा। पीड़ित के सिर में गंभीर चोटें आईं। पीड़ित का आरोप है कि मारपीट कर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई 300 के नीचे; तेज हवाओं से मिली मामूली राहत, आज से छाएगा कोहरा

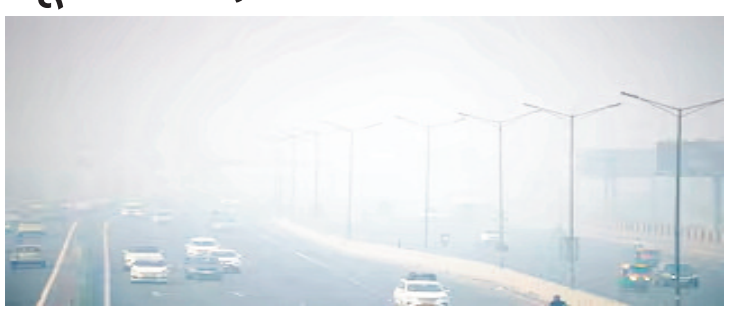

नोएडा। दिल्ली-एनसीआर में कई दिनों से बनी विषाक्त हवा के बीच मंगलवार सुबह लोगों को थोड़ी राहत मिलती दिखाई दी। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही सतही हवाओं ने वायु प्रदूषण को कुछ हद तक कम किया है। हवा की गति बढ़ने से प्रदूषक कण ऊपरी वायुमंडल में फैलने लगे हैं, जिसका असर सीधे तौर पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के स्तर पर देखा जा रहा है। शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी तक दर्ज किया जा रहा था, लेकिन आज कई मॉनिटरिंग स्टेशन 300 के नीचे आते दिखाई दिए।

नोएडा में एक्यूआई में सुधार, कुछ स्टेशनों पर स्तर 255 के करीब सीपीसीबी और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानक स्टेशनों के अनुसार नोएडा के सेक्टर-62 में एक्यूआई 255, सेक्टर-125 में एक्यूआई 313 और सेक्टर-116 में एक्यूआई 307 दर्ज किया गया। दिल्ली में भी कुछ जगहों पर स्थिति सुधरी दिखाई दी है। दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआई 300 के नीचे दर्ज किया गया। उपलब्ध डेटा के अनुसारः पुसा – 270, शादीपुर –239, विवेक विहार -323, वजीरपुर – 320 और आरके पुरम – 313 एक्यूआई दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमानः कल से छाएगा कोहरा। आईएमडी की मौसम रिपोर्ट के अनुसार, 9 दिसम्बरः हल्की धुंध, तापमान अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस सुबह के समय हवा की गति 15-25 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। 10 दिसंबर को शैलो फॉग (हल्का कोहरा) रहने की संभावना है और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसी तरह 11 दिसम्बर को घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना हैं। मौसम विभाग का कहना है कि कल से सुबह के समय कोहरा बढ़ेगा, जिससे दृश्यता प्रभावित होने की संभावना है। तेज हवाएँ धीमी पड़ते ही प्रदूषण दोबारा बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है।

कुख्यात अपराधी सुंदर भाटी समेत 10 को नौ साल की सजा

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में सोमवार को कुख्यात अपराधी सुंदर भाटी समेत 10 दोषियों को नौ-नौ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पुलिस प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में कासना थाना पुलिस ने सुंदर भाटी और उसके गिरोह के 10 सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने सुंदर भाटी (निवासी घंघोला), सिंहराज, विकास पंडित, योगेश, ऋषिपाल, बॉबी उर्फ शेर सिंह, सोनू, यतेन्द्र चौधरी, अनूप भाटी और दिनेश भाटी को दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि इनमें से सात आरोपी पहले से ही जेल में बंद थे। सोमवार को सुनवाई में सुंदर भाटी, सिंहराज और ऋषिपाल पेश हुए, सजा सुनाई जाने के बाद सिंहराज और ऋषिपाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि सुंदर भाटी को रिहा कर दिया गया, क्योंकि वह इस मामले में जेल में रहते हुए अपनी सजा पहले ही पूरी कर चुका था।

संपादकीय

भारतीय रोजगार का करार

भारतीय कामगारों के लिए एक सुखद खबर है। रूस 10 लाख भारतीय कामगारों, कुशल और अर्द्धकुशल, को रोजगार देगा। भारत भी रूसी कामगारों को रोजगार के अवसर मुहैया कराएगा, लेकिन यह रूस की विकराल समस्या है। दोनों देशों के बीच 'श्रम गतिशीलता समझौता' तय हुआ है, उसी के तहत रूस भारतीयों को नौकरियां देगा। विदेश और श्रम मंत्रालयों ने इस करार की पुष्टि की है। मंत्री और मंत्रालय के स्तर पर शिखर संवाद हो चुका था। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच संवाद होने के बाद करार को हरी झंडी दे दी गई। अब यह यथाशीघ्र लागू हो जाएगा। रूस भारत के राजमिस्त्री, वेल्डर, आईटी इंजीनियर, नर्स के अलावा, निर्माण, तेल-गैस, कृषि, वस्त्र, बैंकिंग और स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में भी भारतीयों की सेवाएं लेगा। भारतीयों के रोजगार, नौकरियां सुरक्षित और कानूनन होंगी। कामगार एक देश से दूसरे देश में सहजता, सुगमता से आवाजाही कर सकेंगे। यही इस समझौते का मकसद और मर्म है। रूस अविलंब इस करार को लागू इसलिए करना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों की पाबंदियों के कारण रूस में श्रम-संकट विकराल है। रोजगार का भाव ही ठप पड़ा है। दूसरी ओर भारत में 65 फीसदी आबादी ऐसी है, जिसकी औसत उम्र 35 साल या उससे कम है। भारत में बेरोजगारी एक विकट और संवेदनशील समस्या है। रूस में ये नियुक्तियां और अनुबंध सरकार के स्तर पर किए जाएंगे। दरअसल इन नियुक्तियों को इमिग्रेशन, अर्थात अप्रवास, समझने की गलती न की जाए। नियुक्तियां जरूरत के मुताबिक अस्थायी अथवा दीर्घकालिक हो सकती हैं। रूस में भारतीय कामगार को सामाजिक सुरक्षा के अलावा बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं और कानूनी सुरक्षा एवं संरक्षण आदि भी दिए जाएंगे। रूस भारत की आईटीआई, इंजीनियरिंग की डिग्री और डिप्लोमा के अलावा पेशेवर कुशलता को भी मान्यता देगा, ताकि कामगारों को उचित रोजगार और मेहनताना आदि मिल सके। इस करार से भारत को कई फायदे होंगे। रोजगार तो उपलब्ध होगा ही। फिलहाल रूस में 1 लाख से अधिक भारतीय बसे हैं और वे विभिन्न व्यवसायों में काम कर रहे हैं। ये कामगार रूस के कई इलाकों में फैले होंगे, लिहाजा आबादी के मद्देनजर वे एक बेहतर संतुलन साबित हो सकते हैं। दरअसल भारत के लिए रूस एक सार्थक बाजार बनकर उभरेगा। इस करार से हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि भारतीय कामगार रूस से पैसा कमा कर भारत भेजेंगे। रूस में भारत की अपेक्षा वेतनमान काफी अधिक है। करार के बाद भर्ती की प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी होगी। एक आधिकारिक पोर्टल होगा। उसमें अवैध एजेंटों का धंधा बंद हो जाएगा और भारतीय युवाओं की जान जोखिम में नहीं पड़ेगी। सिर्फ यही नहीं, रूस में 'मेक इन इंडिया' के लिए भी बाजार मिलेगा। जब भारतीय कामगार रूस जाएंगे, तो भारतीय उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी, लिहाजा हमारे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। हमारे कामगारों को राजमिस्त्री, बिजलीवाले, वेल्डर, पेंटर के काम खूब मिलेंगे, क्योंकि रूस में इनकी मांग बहुत है। तेल और गैस क्षेत्रों में काम करने के मौके मिलेंगे।

मानवाधिकार दिवस (10 दिसम्बर) पर विशेष

लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के हो सकारात्मक प्रयास

भारत में 28 सितम्बर 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में आया। 12 अक्टूबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। आयोग के कार्यक्षेत्र में नागरिक और राजनीतिक के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं। जैसे बाल मजदूरी, स्वास्थ्य, भोजन, बाल विवाह, महिला अधिकार, हिरासत और मुठभेड़ में होने वाली मौत, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकार। पूरे विश्व में इस बात को अनुभव किया गया है और इसीलिए मानवीय मूल्यों की अवहेलना होने पर वे सक्रिय हो जाते हैं। इसके लिए हमारे संविधान में भी उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 39, 43, 45 देश में मानवाधिकारों की रक्षा करने के सुनिश्चित हैं। कहने में मानवाधिकार शब्द बहुत बड़ा है। क्योंकि मानवाधिकारो से हर व्यक्ति का हित जुड़ा होता है। आज के दौर में कोई भी मानव को उनके वास्तविक अधिकार नहीं देना चाहता है। राजनेता मानव अधिकार की बात तो जोरशोर से करते हैं। मगर जब अधिकार देने की बारी आती है तो पीछे खिसकने लगते हैं। राज नेताओं को पता है कि यदि लोगों को उनके अधिकार मिल गये तो तो उनकी नेतागिरी बन्द हो जायेगी।

-रमेश सर्राफ धमोरा-

हम 10 दिसंबर को मानवाधिकारों का उत्सव मनाते है। उस दिन की स्मृति में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। यह घोषणा हमारे समाजों के मानवाधिकार ढांचे की रीढ़ है, जहां हममें से प्रत्येक को बिना किसी भेदभाव के शांति और सुरक्षा के साथ रहने और फलने-फूलने का अधिकार है। 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष की 10 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाना तय किया था। 75 वर्ष पहले पारित हुआ विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र एक मील का पत्थर हैं। जिसने समृद्धि, प्रतिष्ठा व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति मानव की आकांक्षा प्रतिबिंबित की है। आज यही घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बुनियादी भाग है। 10 दिसंबर 2025 को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक प्रतिज्ञाओं में से एक मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 77वीं वर्षगांठ है। 2025 में मानवाधिकार दिवस की थीम हमारी रोजमर्रा की अनिवार्यताएं, तीन सरल सत्यों पर जोर देती हैं। मानवाधिकार सकारात्मक हैं, मानवाधिकार आवश्यक हैं, और मानवाधिकार प्राप्य हैं।

मानव अधिकार वे मूल अधिकार हैं जो इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति के पास हैं। मानवाधिकार मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता हैं। मानवाधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार और बहुत कुछ शामिल हैं। बिना किसी भेदभाव के हर कोई इन अधिकारों का हकदार है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन मानवाधिकारों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्त्रोत रहा है। कुछ अधिकार ऐसे होते है जो व्यक्ति को जन्मजात मिलते है। उन अधिकारों का व्यक्ति के आयु, प्रजातीय मूल, निवास-स्थान, भाषा, धर्म पर कोई असर नहीं पड़ता।

देश के विशाल आकार व विविधता तथा सम्प्रभुता सम्पन्न धर्म-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा तथा एक भूतपूर्व औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास के परिणामस्वरूप भारत में मानवाधिकारों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमें धर्म की स्वतंत्रता भी अंतर्भूक्त है। संविधान की धाराओं में बोलने की आजादी के साथ-साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन तथा देश के अन्दर एवं बाहर आने-जाने की भी आजादी दी गई है। भारतीय परिदृश्य में यह समझ पाना थोड़ा मुश्किल हैकि क्या वाकई में मनुष्य के लिए चिन्हित किये गए मानवाधिकारों की सार्थकता है।

भारत में 28 सितम्बर 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में आया। 12 अक्टूबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। आयोग के कार्यक्षेत्र में नागरिक और राजनीतिक के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं। जैसे बाल मजदूरी, स्वास्थ्य, भोजन, बाल विवाह, महिला अधिकार, हिरासत और मुठभेड़ में होने वाली मौत, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकार। पूरे विश्व में इस बात को अनुभव किया गया है और इसीलिए मानवीय मूल्यों की अवहेलना होने पर वे सक्रिय हो जाते हैं। इसके लिए हमारे संविधान में भी उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 39, 43, 45 देश में मानवाधिकारों की रक्षा करने के सुनिश्चित हैं।

कहने में मानवाधिकार शब्द बहुत बड़ा है। क्योंकि मानवाधिकारो से हर व्यक्ति का हित जुड़ा होता है। आज के दौर में कोई भी मानव को उनके वास्तविक अधिकार नहीं देना चाहता है। राजनेता मानव अधिकार की बात तो जोरशोर से करते हैं। मगर जब अधिकार देने की बारी आती है तो पीछे खिसकने लगते हैं। राज नेताओं को पता है कि यदि लोगों को उनके अधिकार मिल गये तो तो उनकी नेतागिरी बन्द हो जायेगी। हमारे देश के संविधान में मानव को बहुत सारे अधिकार दिये गये हैं। मगर उन पर अमल नहीं हो पाता है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिये बनाये गये कानून महज कागजो में सिमट कर रह जाते हैं।

इतिहास गवाह है की भारत ने कभी भी संस्कृति, धर्म या अन्य कारकों के आधार पर दूसरों को अपने अधीन करने की कोशिश नहीं की है। भारत एक ऐसा देश है जिसके मूल में मानवाधिकार की अवधारणा है। भारत के लोग मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं और उनकी रक्षा करने का संकल्प भी लेते हैं। भारत विश्व स्तर पर आज भी मानवाधिकार का समर्थन करता रहा है। मानवाधिकार दिवस की नींव विश्व युद्ध की विभीषिका से झुलस रहे लोगों के दर्द को समझ कर और उसको महसूस कर रखी गई थी। किसी भी इंसान की जिन्दगी, आजादी, बराबरी और सम्मान के अधिकार का नाम ही मानवाधिकार है। भारतीय संविधान इन अधिकारों की न सिर्फ गारंटी देता है, बल्कि इसे तोडने वाले को अदालत सजा भी देती है।

पूरी दुनिया में मानवता के खिलाफ हो रहे जुल्मों-सितम को रोकने, उसके खिलाफ संघर्ष को नई परवाज देने में इस दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर शख्स को बराबरी का अधिकार देना लोकतंत्र का अहम घटक है। यही वजह है कि आज ज्यादातर सरकार इस अधिकार को कायम करने की कोशिश कर रही है। इंसानी अधिकार हमारे अस्तित्व और दुनिया में आत्मसम्मान से रहने की गारंटी होते हैं। हमारी भौतिक और आत्मिक सुरक्षा बरकरार रखते हुए लगातार तरक्की में अहम होते हैं। इसके अंतर्गत भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण से रक्षा का अधिकार, प्रवास का अधिकार, बाल शोषण, उत्पीडन पर रोक, महिला हिंसा, असमानता, धार्मिक हिंसा पर रोक जैसे कई मजबूत कानून बनाए गए हैं। यही वजह है कि हर लोकतांत्रिक देश मानवाधिकार अधिकारों की सशक्त पैरवी करते नजर आते हैं।

इस दुनिया में जो भी मानव जन्म लेता है उसके साथ उसके कुछ अधिकार भी वजूद में आते हैं। कुछ अधिकार हमें परिवार देता है तो कुछ समाज, कुछ अधिकार हमारा मुल्क देता है, तो कुछ दुनिया। लेकिन आज भी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो या तो अपने अधिकारों से अंजान है या उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कभी जात के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर, कभी लिंग भेदभाव के जरिए तो कभी रंग भेद नीति को अपनाकर लोगों के इन अधिकारों को कुचला जा रहा है। हर तबके, हर शहर और दुनिया के कोने-कोने में किसी न किसी वजह से लोगों को बराबरी के हक से महरूम रखने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में हुई बड़ी से बड़ी क्रांति के पीछे अधिकारों का हनन ही अहम वजह रही है। हमेशा ही अपने अधिकारों के लिए इंसान को लंबी जंग लडनी पड़ी है। दुनिया में तमाम जगह लोगों ने अपन हक की लड़ाई में लाखों कुर्बानियां दी हैं और आज भी बहुत से लोग अपने अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं।

मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाये गए और उनको लागू करने या करवाने के लिए प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन वह सिर्फ कागजी दस्तावेज बन कर रह गए हैं। समाज में मानवाधिकारों के होने वाले उल्लंघन के प्रति अगर मानव ही जागरूक नहीं है तो फिर इनका औचित्य क्या है? देखे तो पता चलेगा की कितने मानवाधिकारों का हनन मानव के द्वारा ही किया जा रहा है। मानव के द्वारा मानव के दर्द को पहचानने और महसूस करने के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं होती है। अगर हमारे मन में मानवता है ही नहीं तो फिर हम साल में पचासों दिन ये मानवाधिकार का झंडा उठा कर घूमते रहें कुछ भी नहीं किया जा सकता है।

सरकार भी मानवाधिकारो का हनन रोक पाने में पूर्णतया सफल नहीं हो पा रही है। देश में आये दिन मानवाधिकार हनन की घटनायें घटित होती रहती है। मगर सरकारी स्तर पर शख्त कार्यवाही अमल में नहीं लायी जाती है। जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति पर रोक लग सके। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमाम प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अन्तरर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सरकारी और गैर सरकारी मानवाधिकार संगठनों के बावजूद मानवाधिकारों का लगातार हनन होता रहता है।

गोवा हादसाः झुलसती संवेदनाएं और नाकाम होती व्यवस्था

-ललित गर्ग-

अ एक बार फिर एक भीषण आग ने 25 मासूम जिंदगियों को छीन लिया। गोवा के नाइट क्लब में हुई यह त्रासदी केवल आगजनी नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की जड़ता, गैर-जिम्मेदारी और नैतिक पतन की ज्वलंत मिसाल है। गोवा का जो नाइट क्लब आग की चपेट में आया, वह नियमों की अनदेखी करके तो चलाया ही जा रहा था, उसमें आग से बचाव के उपाय भी नहीं किए गए थे। रही-सही कसर इससे पूरी हो गई कि नाइट क्लब में आने और जाने का रास्ता बेहद संकरा था। आग की चपेट में आने वालों की संख्या इसलिए अधिक बढ़ गई, क्योंकि बचने के लिए उन्होंने जिस रास्ते को सुरक्षित समझा, वहां पहले से ही लोग फंसे हुए थे। इस तरह से आनंद और उत्सव का स्थल अचानक जीवन समाधि में बदल गया, वह अनेक सवाल हमारे सामने खड़े करता है, क्या हम सीखने की क्षमता खो चुके हैं? क्यों हर हादसे के बाद जांच समितियां बनती हैं, मुआवजा घोषित होता है, कुछ दिन हंगामा होता है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है? पूर्व में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, सूरत और अनेक शहरों में समान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। होटल, मॉल, थिएटर, अस्पताल, फैक्ट्री, कोचिंग सेंटर-लापरवाही की आग में झूलसनों वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हमारी संवेदनशीलता का स्तर छोटा होता जा रहा है। आगजनी की घटनाओं का सिलसिला तो लगातार है, परंतु सुरक्षा मानकों के प्रति हमारी उदासीनता और घोर लापरवाही भी उतनी ही स्थायी है। यह बात स्पष्ट है कि हादसे किसी तकनीकी गलती का परिणाम भर नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक मिलीभगत की देन भी हैं।

गोवा अपनी पहचान पर्यटन से बनाता है। नाइट लाइफ, समुद्री तटों का आनंद, मनोरंजन गतिविधियां और विदेशी पर्यटक इसका स्वाभाविक आकर्षण हैं। ऐसे प्रदेश में इस प्रकार का हादसा केवल मानवीय त्रासदी नहीं, बल्कि छवि और अर्थव्यवस्था का गहरा नुकसान भी है। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री पहले ही प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा को लेकर चुनौतियों से जूझ रही है। यह घटना विश्व के सामने एक सवाल बनकर खड़ी है-क्या भारत सुरक्षित पर्यटन देश है? क्या यहां गैर-जिम्मेदाराना ढांचे और भ्रष्ट तंत्र के बीच किसी का जीवन सुरक्षित रखा जा सकता है? इस प्रकार के हादसों में दो बड़े चरित्र सामने आते हैं-सरकार की सुस्ती और आयोजकों की लालचपूर्ण मानसिकता। अधिकांश नाइट क्लब, बार, पार्क या मनोरंजन स्थल ऐसे होते हैं जहां प्रवेश शुल्क, अवैध संचालन और आर्थिक लाभ का बड़ा खेल चलता है। इमारतों की मंजूरी, फायर सुरक्षा की अनुमति, बिजली के तारों का रखरखाव, निकास मार्ग-ये सभी चीजें फाइलों में तो दर्ज होती हैं, लेकिन जमीन पर गायब रहती हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की सजगता की जगह 'संबंध' और 'सुविधा शुल्क' काम करता है। निरीक्षण के नाम पर औपचारिकता ढहती है और बीते हुए हादसे केवल याद बनकर रह जाते हैं।

नाइट क्लब तक पहुंचने का रास्ता इतना संकरा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 400 मीटर दूर खड़ा होना पड़ा। सजावट के लिए ताड़ के सूखे पत्तों का इस्तेमाल किया गया था, जिसने आग और भड़का दी। भीड़भाड़ वाली जगहों पर एंट्री से ज्यादा महत्वपूर्ण इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इस क्लब में लगता है कि इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कई लोग भटक कर किचन में पहुंच गए, जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। यह नाइटक्लब बिना मंजूरी के चल रहा था। लोकल अथॉरिटी के मुताबिक, निर्माण अवैध था।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर हम हादसों को नियति क्यों मान लेते हैं? हर घटना के बाद नेताओं के बयान आते हैं 'दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा', 'उच्च स्तरीय जांच की जाएगी', 'मुआवजा दिया जाएगा', लेकिन क्या कभी हमने दोषियों को सजा होते देखा है? कभी किसी अधिकारी को बर्खास्त होते देखा है? क्या किसी क्लब या होटल की अनुमति स्थायी रूप से रद्द की गई? जवाब अधिकतर 'नहीं' है। यही वह सत्य है जो बताता है कि हमारा समाज हादसे को दुख तो मानता है पर समस्या नहीं मानता। अजीब विडंबना यह है कि हादसे के शिकार गरीब या आम नागरिक होते हैं, लेकिन इस त्रासदी से गुजरी व्यवस्थाओं को कोई चोट नहीं लगती। वे फिर उठते हैं, नए सजावटी बोर्ड लगा लेते हैं और जनता को फिर से आकर्षित कर लेते हैं। व्यवस्था में भ्रष्टाचार और मानव-मूल्यों का ह्रास दोनों मिलकर ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं। यह केवल प्रशासनिक नाकामी नहीं, बल्कि सामूहिक नैतिक ह्रास भी है। आयोजक केवल लाभ देखते हैं; प्रशासन केवल कागजों पर निशान देखता है; समाज घटना को क्षणिक दुख समझकर भूल जाता है।

वैश्विक स्तर पर देखें तो किसी भी विकसित या उत्तरदायी समाज में जन-स्थलों पर सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। नियमित निरीक्षण, कठोर दंड, मानकों का अनिवार्य पालन और पारदर्शिता बुनियादी तत्व हैं। भारत में ये मानक केवल कानूनी पुस्तकों में रहते हैं। सवाल यह नहीं कि हादसे क्यों होते हैं, सवाल यह है कि सीख क्यों नहीं ली जाती। गोवा का यह हादसा एक चेतावनी है, अकेले गोवा के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए। हम विकास, पर्यटन और आधुनिक जीवनशैली की बात करते हैं, लेकिन सुरक्षा, नियंत्रण और मानवीय संवेदनशीलता को हाशिए पर छोड़ देते हैं। यह घटना बताती है कि यदि व्यवस्था की लापरवाही और लालच के बीच नागरिक की सुरक्षा कुचलती रही तो हम आधुनिक ढांचे बनाकर भी असुरक्षित रहेंगे। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके नागरिकों की सुरक्षा पर टिकी होती है, न कि केवल चमक-दमक पर।

गोवा घटना ने सरकार की छवि को ध्वस्त किया है। पर्यटन उद्योग की नींव हिलाई है और नागरिक विश्वास को चोट पहुंचाई है। गोवा के जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा 16 प्रतिशत से ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी से सितंबर के बीच 6.23 प्रतिशत ज्यादा टूरिस्ट गोवा पहुंचे। यदि घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनी है तो कुछ कठोर कदम उठाने होंगे, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, वास्तविक निरीक्षण प्रणाली, भ्रष्टाचार पर अंकुश और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर दंड। परंतु दुख यह है कि हमारा इतिहास बताता है, हम कठोर कदम उठाने से बचते हैं। आज इस त्रासदी के बाद शोक जताना पर्याप्त नहीं है। इस पर गंभीर चिंतन जरूरी है। हम केवल जिम्मेदारी टाल देने की प्रवृत्ति में नहीं जी सकते। हर हादसा हमें यही याद दिलाता है कि सुरक्षा संस्कृति, जिम्मेदार शासन और नैतिक व्यवसायिक आचरण के बिना कोई भी समाज सुरक्षित नहीं हो सकता।

गुरु ही संस्कार को परिष्कृत करता है

गुरु तत्व प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में व्याप्त होता है। लौकिक ज्ञान से लेकर ब्रहमज्ञान तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक गुरु तत्व की उपस्थिति बनी रहती है। कोई शिक्षा गुरु होता है, तो कोई कुल गुरु। वस्तुतः गुरु सांस्कृतिक धरोहर है। गुरु ही संस्कार को परिष्कृत करता है। गुरु के आगमन से शिष्य के जीवन में वैचारिक परिवर्तन होता है। शिष्य की मनोदशा बदलती है। यह सब गुरु के अनुग्रह से संभव हो पाता है। स्वयं तप चुका गुरु ही, शिष्य को तपा सकता है यानी उसमें जाग्रति ला सकता है। तपने का तात्पर्य है-जागृति।

स्वयं को समझने की शक्ति और सत्य को पाने की लालसा। गुरु केवल शिष्य को ज्ञानोपदेश नहीं देता है, बल्कि उसके अंदर अभिनव प्राण फूंकने का कार्य करता है। सच्चा शिष्य हमेशा ही अपने गुरु के प्रेम में भाव-विभोर रहता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि वह जानता है कि जो सजगता, सतर्कता और सचेतनता उसके पास है वह गुरु के अनुग्रह से है। सद्गुरु चाहे तो शिष्य की जीवन दशा और दिशा, दोनों ही बदल सकता है। सद्गुरु अयोग्य शिष्य को भी योग्य बनाए रखने के लिए सदैव उसके पीछे लगे रहते हैं। वे जानते हैं कि शिष्य को क्या चाहिए। वह उसकी पात्रता के अनुसार उसे देते भी हैं। धर्मगुरुओं की वीथिकाएं, जो एक दिशा से दूसरी दिशा तक फैली हुई हैं। ये सब गुरुओं के विधानों के प्रतीक ही हैं। गुरु अपने शिष्य को कभी ओझल नहीं होने देता है।

प्राचीन ऋषि-मुनियों ने न ही गुरु परंपरा को ओझल होने दिया और न ही दिव्य शिष्य को। जहां प्रेम है वहां गुरु का प्रादुर्भाव है। गुरु बनने के साथ-साथ उसकी अपने प्रति तो जवाबदेही होती है, साथ ही समाज के प्रति उसे अपने दायित्व का बोध भी होना चाहिए। आज के समय में एक सद्गुरु की शायद आवश्यकता और भी बढ़ गई है, क्योंकि समाज निरंकुश होता जा रहा है। आपसी प्रेम और भाईचारा कम हो रहा है। कुछ अच्छा सोचें और करें। शायद यही समय की सच्ची मांग है। ज्ञान के बाद जो दीक्षा दे, वही सद्गुरु है। सद्गुरु ही अपने शिष्य को ईश्वर की अनुभूति करा सकता है। तभी तो भारतीय धर्म-दर्शन में सद्गुरु की महिमा का बखान किया गया है।

आज का इतिहास

1582 - फ्रांस ने ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करना शुरु किया।
1684 - एडमंड हैली ने गेरुम में पेपर डी मोटू कॉर्पोरम प्रस्तुत किया, जिसमें आइजैक न्यूटन के केपलर के नियमों को उनके टॉगविटी के सिद्धांत, रॉयल सोसाइटी से व्युत्पन्न किया गया था।
1799 - फ्रांस पहला ऐसा देश बन गया जिसने वजन और उपायों के लिए मीट्रिक प्रणाली को प्रणाली को अपनाया।
1817 - मिसिसिपी को अमेरिका के 20 वें राज्य के रूप में स्वीकार किया।
1861 - दक्षिणी वियतनाम में एक उपनिवेश-विरोधी छापामार न्युन ट्रुंग ट्राक के नेतृत्व में बलों ने फ्रांसीसी लोरचा एलसपेरेंस को डूबो दिया।
1884 - हकलबेरी फिन के मार्क ट्वेन एडवेंचर्स पहली बार लंदन में प्रकाशित हुआ।
1884 - अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेनवास द्वारा हकल बेरी फिन का एडवेंचर्स यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में पहली बार प्रकाशित हुआ।
1896 - स्वेडन के रसायनशास्त्री व नोबेल प्राइज के संस्थापक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का निधन हुआ।
1896 - अल्फ्रेड जरी के नाटक उबू रोई ने पेरिस में अपने एकमात्र प्रदर्शन डे'एतेरे डी ल्युव्रे का प्रदर्शन किया, जो बदनाम करने के लिए एक दंगाई प्रतिक्रिया का कारण बना।
1898 - पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और स्पेनी-अमेरिकी युद्ध समाप्त किया गया।
1898 - पेरिस संघि के बाद स्पेन-अमेरिकी युद्ध समाप्त हुआ।
1901 - उनके संस्थापक स्वीडिश रसायनज्ञ और उद्योगपति अल्फ्रेडनोबेल की 1896 की मृत्यु की सालगिरह पर पहले नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे।
1901 - पहला नोबेल पुरस्कार समारोह, अल्फ्रेड नोबेल की मौत की पांचवीं वर्षगांठ पर स्टॉकहोम में आयोजित किया गया।
1902 - अफ्रीका में स्थित नाइल नदी पर पहला असवान बांध बनाया गया।
1902 - तस्मानिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया।
1903 - पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मोहन के विरासत से विकास मंत्र से अब बुंदेलखंड को मिलेगी नई रफ्तार

-हर्षवर्धन पान्डे-

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है, तब से उनकी कार्यशैली और दूरदर्शिता ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। जल की कमी, खराब सड़कें और औद्योगिक पिछड़ापन दशकों से बुंदेलखंड की सबसे बड़ी त्रासदी रहे हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पद संभालते ही प्रदेश के हर क्षेत्र को समान रूप से विकसित करने का संकल्प लिया है। डॉ. मोहन यादव ने सत्ता संभालते ही बुंदेलखंड को अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा। बुंदेलखंड क्षेत्र, जो दशकों से उपेक्षा और पिछड़ेपन का दंश झेलता आ रहा था, अब मोहन के नेतृत्व में एक नई उड़ान भरने को तैयार है।

बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या जल संकट रहा है। इसे प्राथमिकता देते हुए मोहन सरकार ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति दी है। एक तरफ केन-बेतवा लिंक परियोजना को अभी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है वहीं दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर जिलों में कई सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसी प्रकार नदियों और तालाबों के जीर्णोद्धार के साथ-साथ जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण भी तेज हुआ है। पिछले दो वर्षों में सरकार ने न केवल केंद्रीय योजनाओं को गति दी, बल्कि राज्य स्तर पर अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। 2024 में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना सरीखी राष्ट्रीय परियोजना को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र और राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित कर तेजी से आगे बढ़ाया है। इस परियोजना से बुंदेलखंड के 13 जिलों में 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। आने वाले दिनों में नर्मदा-सोनार लिंक परियोजना भी बुंदेलखंड के लिए वरदान साबित होगी जिससे यहाँ का जलसंकट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सोनार नदी को नर्मदा से जोड़ने का सर्वे जल्द शुरू होगा। इससे बुंदेलखंड की सूखी नदियां कभी न सूखेंगी और क्षेत्र की धरती पहले से कहीं अधिक उपजाऊ बनेगी। इसी तरह से पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना और ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना भी बुंदेलखंड के पानी के संकट को समाप्त कर देंगी। महाराष्ट्र के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं जिससे बुंदेलखंड के समूचे अंचल में पेयजल और सिंचाई की समस्या हल हो जाएगी।

बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी रही है कि यहां पहुंचना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसका कायाकल्प करने की ठानी दशकों से सूखा और पिछड़ापन इस क्षेत्र की पहचान बने थे अब इस क्षेत्र में पिछले डेढ़ वर्षों में सड़क, रेल और हवाई संपर्क ने अभूतपूर्व विकास किया है। ख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुंदेलखंड को कनेक्टिविटी की नई गति दी है। सागर-दमोह-कटनी-लखनादौन को जोड़ने वाली चार लेन सड़क परियोजना को मंजूरी हो या टीकमगढ़ से सागर तक नई रेल लाइन और छतरपुर-टीकमगढ़-झांसी रेल लाइन का विस्तार कनेक्टिविटी में अब बुंदेलखंड किसी भी तरह से पीछे नहीं है। खजुराहो, दतिया सागर और ग्वालियर एयरपोर्ट के उन्नयन और नए हवाई अड्डों की कार्ययोजना ने बुंदेलखंड की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत किया है। डेढ़ दशक से रुके प्रोजेक्ट अब रिकॉर्ड समय में पूरे हो रहे हैं। बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी बेहतर होने से यहाँ पर्यटन, उद्योग और रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। बेहतर कनेक्टिविटी होने से यहाँ पर अब परियोजनाएं न केवल आवागमन को आसान बनाएंगी, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा देंगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प ने बुन्देलखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में कई ऐतिहासिक पहल की हैं। चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस और पीजी मेडिकल सीटों की संख्या में वृद्धि से लेकर तकनीकी रूप से उक्त स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तक राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। एक तरह जहाँ पन्ना, दमोह और टीकमगढ़ में नए मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं वहीं सागर में कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा के साथ ही हर जिले में उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना जैसे कदम बुंदेलखंड के युवाओं को को घर के पास ही अच्छी शिक्षा और इलाज की सुविधा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के मिशन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुंदेलखंड को शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वे आने वाले वर्षों में बुंदेलखंड की सूरत को बदलकर रख देंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुंदेलखंड को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया जा चुका है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना और निवेशकों को आकर्षित करना इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य था। इस कॉन्क्लेव में लगभग 23, 000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और 27, 800 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए। डिफेंस कॉरिडोर के तहत टीकमगढ़ और झांसी में कई बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य प्रगति पर है वहीँ खजुराहो, ओरछा, पन्ना टाइगर रिजर्व और चंदेरी के पर्यटन सर्किट को विश्वस्तरीय बनाने की कार्ययोजना पर राज्य सरकार काम कर रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे जैसे बड़े प्रोजेक्ट से यह क्षेत्र दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ेगा जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पलायन की समस्या कम होगी।

विरासत से विकास के अपने मिशन और सांस्कृतिक धरोहरों को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 8-9 दिसंबर को खजुराहो में आयोजित होगी। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में विख्यात खजुराहो की प्राचीन मंदिर वास्तुकला और चंदेल राजवंश की अमर विरासत के बीच होने वाली यह बैठक न केवल प्रशासनिक समीक्षा का मंच बनेगी, बल्कि विरासत से विकास के संकल्प को मजबूत करने का प्रतीकात्मक संदेश भी देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत भी और विकास भी के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में यह कदम मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्व की बैठकों में बार-बार जोर दिया है कि राज्य का विकास प्राचीन गौरव को नष्ट किए बिना ही संभव है। पचमढ़ी और इंदौर जैसी पिछली कैबिनेट बैठकों की तर्ज पर खजुराहो में भी सांस्कृतिक पुनरुत्थान और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संयोजन पर विशेष फोकस होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और स्थानीय कारीगरों के लिए कौशल विकास योजनाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। यह आयोजन न केवल प्रशासनिक दक्षता को परखेगा, बल्कि मध्य प्रदेश को विरासत से विकास की मिसाल के रूप में स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बुंदेलखंड के प्रति विशेष लगाव और संवेदनशीलता साफ दिखाई देती है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक आदित्य वशिष्ठ द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस, बी-42 सेक्टर -7 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से मुद्रित व ए-152, सैक्टर 63, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से प्रकाशित।
संपादक - आदित्य वशिष्ठ   कानूनी सलाहकार-पवित्र मोहन शर्मा   आर.एन.आई.- UPHIN/2023/84499
इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी होंगे।   e-mail: Jbttimes2021@ gmail. Com

'वंदे मातरम्' पर चर्चा से आगामी पीढ़ियों को इसके असली महत्व को समझने में मिलेगी मदद : शाह

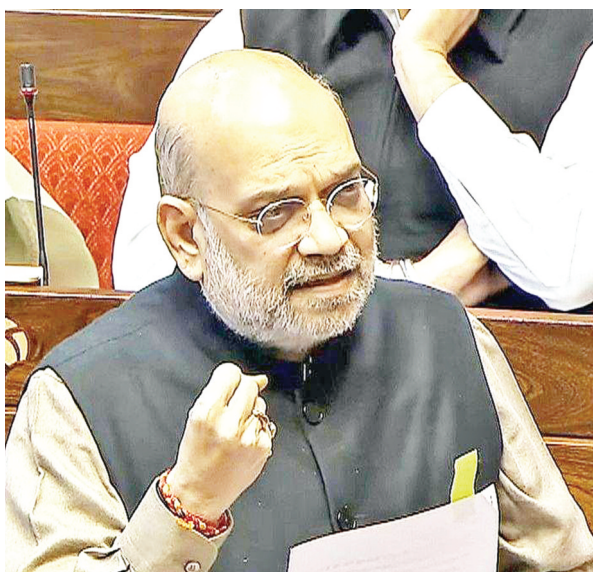

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि संसद के दोनों सदनों में इस अमर कृति पर विमर्श आने वाली पीढ़ियों को इसके वास्तविक महत्व, गौरव और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने का कार्य करेगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत माता के प्रति भक्ति, कर्तव्य और समर्पण की भावना का शाश्वत प्रतीक है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में देश की आत्मा को जागृत किया। शाह ने कहा कि उस दौर में वंदे मातरम् देश को आजाद कराने का कारण बना था और अमृतकाल में यह देश को विकसित तथा महान बनाने का नारा बनेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वंदे मातरम् पर चर्चा को बंगाल चुनाव से जोड़ने वाले लोग इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह विषय राजनीति से परे राष्ट्रीय गौरव का विषय है। गृहमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम् की प्रासंगिकता उसकी रचना के समय भी थी, आजादी के आंदोलन में भी थी, आज भी है और 2047 में विकसित भारत के निर्माण के समय भी बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जहां भी देशभक्त एकत्र होते थे, उनकी हर बैठक की शुरुआत वंदे मातरम् के साथ होती थी।

आज भी सीमा पर जब वीर जवान सर्वोच्च बलिदान देते हैं, तब उनकी जुबान पर एक ही शब्द होता है—वंदे मातरम्। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में जब वंदे मातरम् का गान होता है, तब इंडी गठबंधन के कई सदस्य सदन से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने 1992 का उल्लेख करते हुए कहा कि जब भाजपा सदस्य राम नाईक की पहल और लालकृष्ण आडवाणी के आग्रह पर लोकसभा में वंदे मातरम् का सामूहिक गान फिर शुरू हुआ, तब भी कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ने राष्ट्रीय गीत को भी बांट दिया।

शाह ने कहा कि मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कि अगर कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के तहत वंदे मातरम् को दो हिस्सों में नहीं बांटा होता, तो देश का विभाजन नहीं होता और भारत आज भी पूरा होता। शाह ने कहा कि जब वंदे मातरम् के 50 वर्ष पूरे हुए, तब देश अभी आजाद नहीं हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसकी स्वर्ण जयंती के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे दो अंतरों तक सीमित कर दिया, जिसे उन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत बताया। गृहमंत्री ने वंदे मातरम् की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक महत्ता और इसके राष्ट्रीय प्रभाव का विस्तृत उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को इस रचना को पहली बार सार्वजनिक किया, और कुछ ही समय में यह उत्कृष्ट साहित्यक कृति से आगे बढ़कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणास्रोत और राष्ट्रजागरण का मंत्र बन गई। उन्होंने महर्षि अरविन्द के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि वंदे मातरम् भारत के पुनर्जन्म का मंत्र है। शाह ने बताया कि जब अंग्रेजों ने वंदे मातरम् पर प्रतिबंध लगाया, तब बंकिम बाबू ने कहा था कि उनकी सारी रचनाएं गंगा में बहा दी जाएं, लेकिन वंदे मातरम् का मंत्र सदैव जीवित रहेगा और भारत का पुनर्निर्माण इसी से होगा। उन्होंने कहा कि भारत किसी लड़ाई या वैधानिक समझौतों से नहीं बना, बल्कि इसकी सीमाओं को सदियों पुरानी संस्कृति ने गढ़ा है। इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सबसे पहले बंकिम बाबू ने जागृत किया।

उन्होंने कहा कि भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की मां है, और यह भावना वंदे मातरम् में सर्वाधिक प्रकट होती है। गृहमंत्री ने बताया कि वंदे मातरम् ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पंजाब के गदर आंदोलन से महाराष्ट्र के गणपति उत्सवों तक और तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती के अनुवादों से हिन्द महासागर तक, क्रांति और राष्ट्रभक्ति की चेतना को जगाया। 1907 में 'वंदे मातरम्' नाम से एक अखबार भी निकलता था, जिसके संपादक अरविन्द घोष थे, जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। शाह ने कहा कि रामायण में भगवान श्रीराम से लेकर आचार्य शंकर और चाणक्य तक सभी ने मातृभूमि की महिमा का उल्लेख किया। बंकिम बाबू ने भी इसी चिरंतन भाव को पुनर्जीवित किया और भारत माता को सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के संयुक्त रूप में प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम् 100 वर्ष का हुआ, तब इसका सम्मान नहीं किया गया क्योंकि आपातकाल के दौरान वंदे मातरम् बोलने वालों को जेल में डाल दिया गया था और देश को दमन के वातावरण में बंदी बनाकर रखा गया था। सांसदों से आग्रह करते हुए शाह ने कहा कि युवा पीढ़ी में वंदे मातरम् की भावना, संस्कार और समर्पण को बढ़ावा देना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे के मन में वंदे मातरम् की भावना पुनर्जीवित करें और बंकिम बाबू की उस महान भारत की कल्पना को साकार करें, जिसे उन्होंने इस रचना के माध्यम से देखा था। उन्होंने कहा कि संसद में वंदे मातरम् पर चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि चुनाव निकट हैं, बल्कि इसलिए कि यह गीत भारत की आत्मा है और इसकी गूंज आने वाले विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बनेगी।

रेल राज्य मंत्री सोमन्ना ने तिरुपति–साईनगर शिरडी एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली। रेल राज्यमंत्री वी. सोमन्ना ने मंगलवार को यहां रेल भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तिरुपति–साईनगर शिरडी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह नई साप्ताहिक ट्रेन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र को जोड़ते हुए तीर्थ यात्रा को नई गति देगी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र से शिरडी के लिए पहली सीधी रेल सेवा उपलब्ध कराएगी।

सोमन्ना ने इसे चार राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि भारतीय रेल केवल परिवहन का माध्यम नहीं, बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय जीवनरेखा है। उन्होंने कहा कि तिरुपति और शिरडी जैसे प्रमुख तीर्थस्थलों को सीधे जोड़ने से यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और निर्बाध अंतर-राज्यीय यात्रा सुविधा मिलेगी। लगभग 30 घंटे की यात्रा अवधि वाली यह नई ट्रेन रास्ते में नेल्लोर, गुंटूर, सिकंदराबाद, बीदर, मनमाड़ सहित कुल 31 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी और मार्ग में पारली वैजनाथ जैसे महत्वपूर्ण मंदिर स्थल को भी जोड़ती है।

उन्होंने कहा कि इस सेवा से तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, मार्ग में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और आसपास के क्षेत्रों का संपूर्ण विकास होगा। नई ट्रेन महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक और सिकंदराबाद क्षेत्र को भी सीधा लाभ पहुंचाएगी। सोमन्ना ने बताया कि 2014 के बाद से आंध्र प्रदेश में रेल अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2009–14 के दौरान आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के लिए औसत रेल बजट जहां 886 करोड़ रुपये था, वहीं 2025–26 में यह बढ़कर 9,417 करोड़ रुपये हो गया है। राज्य में वर्तमान में 93 हजार करोड़ रुपये से अधिक के रेल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 2014 के बाद से राज्य में 1,580 किमी नई लाइनों का निर्माण हुआ है, वह भी शत प्रतिशत विद्युतीकरण के साथ। राज्य में अब 73 अमृत स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं जिन पर 3,125 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा 800 फ्लाईओवर और पुल, 110 लिफ्टें, 40 एस्केलेटर लगाए गए हैं तथा 16 वंदे भारत (8 जोड़ी) और 6 अमृत भारत (3 जोड़ी) ट्रेनें शुरू की गई हैं।

तिरुपति में चल रही परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि तिरुपति अमृत स्टेशन का कार्य 312 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। प्रमुख प्रोजेक्ट्स में तिरुपति–पाकाला–कट्पडी डबलिंग (105 किमी – 1,215 करोड़ रुपये), गुडूर–रेनिगुंटा तृतीय लाइन (83 किमी – 875 करोड़ रुपये) और नडिकुड़ी–श्रीकालहस्ती नई लाइन (310 किमी – 5,900 करोड़ रुपये) शामिल हैं। इसके साथ ही विजयवाड़ा–गुडूर तृतीय लाइन (287 किमी – 6,235 करोड़ रुपये) और यर्रपेडु–पुडी बाईपास लाइन (25 किमी – 490 करोड़ रुपये) पर भी कार्य जारी है।

कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री बी. सी. जनार्दन रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा डॉ. मडिला गुरुमूर्ति (सांसद, तिरुपति), बी. कल्याण चक्रवर्ती (एमएलसी), ए. श्रीनिवासुलु (विधायक, तिरुपति), भानु प्रकाश रेड्डी (टीटीडी बोर्ड सदस्य) सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया।

देश रोहिंग्या, बांग्लादेशियों के लिए नहीं, एसआईआर जरूरी : संजय जयसवाल

नई दिल्ली। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत सत्ता पक्ष की ओर से पश्चिम चंपारण से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य संजय जायसवाल ने की। उन्होंने कहा कि यह देश रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए नहीं है और ऐसे में देश में एसआईआर की प्रक्रिया जरूरी है। मतदाता सूची को अपडेट करने से जुड़ी एसआईआर का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में 35 लाख लोगों ने फॉर्म नहीं भरे इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में घुसपैठिए थे। जयसवाल ने एक राष्ट्र एक चुनाव की पहल का भी स्वागत किया और कहा कि विपक्षी सदस्य भले ही कहें लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। अलग-अलग चुनाव कराने से तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है और पूरा संगठन चुनाव में जीत सुरक्षित करने के लिए काम करता है। जायसवाल ने कहा कि हमारे गृहमंत्री आज तक विदेश नहीं गए और प्रधानमंत्री ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। हम चुनाव के दौरान पूरी क्षमता के साथ लगते हैं जबकि विपक्ष के नेता छुट्टियां मना रहे होते हैं।

इंडिगो संकट के बीच कोलकाता एयरपोर्ट की निदेशक ने लिया हालात का जायजा

कोलकाता। देश में इंडिगो की उड़ानों को लेकर पिछले आठ दिनों से चल रही व्यापक अव्यवस्था के बीच कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की निदेशक तन्वी सुन्द्रीयाल ने मंगलवार को हालात का जायजा लिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, इस दौरे का उद्देश्य यात्रियों को सुचारू और निर्बाध सेवा उपलब्ध कराना था।

देश की घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो ने पिछले आठ दिनों में महानगरों सहित देश के कई हवाई अड्डों से हजारों उड़ानें रद्द की हैं। इससे लाखों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि, छह महानगरों में कोलकाता हवाई अड्डा सबसे कम प्रभावित रहा। यहां इंडिगो की कुल 181 उड़ानें प्रतिदिन संचालित होती हैं, जिनमें 91 आगमन और 90 प्रस्थान शामिल हैं। तन्वी सुन्द्रीयाल ने एयरपोर्ट के सभी यात्री संपर्क बिंदुओं का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने इंडिगो के टिकट काउंटर, सहायता डेस्क, चेक-इन काउंटर, प्रस्थान द्वार और कतार प्रबंधन क्षेत्रों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रभावित यात्रियों से सीधे बातचीत कर उनके अनुभव और समस्याओं को समझा। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, अधिकारी ने यात्रियों को आश्वस्त किया कि मंत्रालय स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और संचालन को स्थिर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। निरीक्षण के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), सीआईएसएफ और एयरलाइन प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उड़ान संचालन को सुचारू करने, कर्मचारियों की तैनाती बढ़ाने और यात्री सुविधा उपायों को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गई। कोलकाता एयरपोर्ट की निदेशक ने बताया कि यात्रियों की मदद के लिए कई कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं।

नियम और कानून अहम हैं, लेकिन कानून लोगों पर बोझ नहीं होना चाहिए

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत के लिए मंगलवार को सत्तारूढ़ सरकार के सभी सांसदों की एक बैठक में पीएम मोदी को बधाई दी गई। बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि पीएम मोदी ने सभी सांसदों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए काम करने का निर्देश दिया ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। बता दें पीएम मोदी की यह टिप्पणी इंडिगो के मौजूदा परिचालन संकट के कारण लोगों को हो रही परेशानियों के बीच आई है।

बिहार चुनाव में जीत के लिए पीएम मोदी को माला पहनाकर स्वागत किया गया। उन्होंने एनडीए के सभी सांसदों को देश, अपने निर्वाचन क्षेत्रों और अपने राज्यों के लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। पीएम मोदी ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सुधारों पर बहुत जोर दिया है। रिजिजू ने कहा कि उनका आशय देश के आम लोगों के जीवन को आसान और आरामदायक बनाने के लिए सुधारों से था। हर क्षेत्र में सुधार। रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि सभी को यह तय करना चाहिए कि लोगों को सरकार से कोई परेशानी न हो। नियम और कानून अहम हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल लोगों के लिए परेशानी पैदा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून लोगों पर बोझ नहीं होना चाहिए। इंडिगो एयरलाइन के परिचालन में लगातार हो रही देरी और रद्दीकरण का सिलसिला जारी है, जबकि संकट आठवें दिन भी जारी है। मंगलवार को भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द कर दी गईं। इस बीच, सरकारी प्रतिनिधि और डीजीसीए के अधिकारी इंडिगो के सीईओ से मिलकर स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं।

त्रिपुरा : केंद्र ने 25 नए सड़क प्रोजेक्ट्स के लिए 68.67 करोड़ रुपए की मंजूरी दी

नई दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंगलवार को पीएम-जनमन योजना के रोड कनेक्टिविटी कंपोनेंट के तहत त्रिपुरा में 25 नए सड़क प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। ये प्रोजेक्ट कुल 65.38 किलोमीटर लंबे हैं और इन्हें 68.67 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से डेवलप किया जाएगा। उम्मीद है कि इस कदम से राज्य में, खासकर दूरदराज के आदिवासी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को काफी बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएम-जनमन के रोड कनेक्टिविटी कंपोनेंट के तहत त्रिपुरा के लिए 65.38 किमी लंबाई की 25 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 68.67 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश होगा। मंत्रालय के अनुसार, नई सड़कें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजीएस) से संबंधित 30 बस्तियों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। बेहतर सड़कों से इन समुदायों के रोजमर्रा के जीवन में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे पूरे साल यात्रा आसान और सुरक्षित हो जाएगी। इसमें आगे कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना, दूरदराज के गांवों और शहरी केंद्रों के बीच की दूरी को कम करना। इस पहल का मकसद ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करना और दूरदराज के गांवों को पास के कस्बों और शहरी केंद्रों से जोड़ना है।

भारत माता के प्रति समर्पण, त्याग और अदम्य साहस की शाश्वत भावना है वंदेमातरम् : राधाकृष्णन

नई दिल्ली। राज्यसभा में मंगलवार को 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा से पूर्व, सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में इसे राष्ट्र की आत्मा और स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन बताया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत माता के प्रति समर्पण, त्याग और अदम्य साहस की शाश्वत भावना है, जिसने गुलामी के दौर में करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ जलाए रखी।

सभापति ने कहा कि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह कालजयी गीत उस समय जन्मी जब मातृभूमि पर उपनिवेशवाद का भारी बोझ था, लेकिन देखते ही देखते यह पूरे राष्ट्र की साझा धड़कन बन गया। उन्होंने कहा कि यह गीत धर्म, भाषा और भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोता रहा। राधाकृष्णन ने स्मरण कराया कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वंदे मातरम् केवल प्रेरणा नहीं था, बल्कि कई वीरों की अंतिम पुकार भी—जब वे हंसते-हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए भारत की आज़ादी का स्वप्न दिल में लिए इसे उच्चारित करते थे। उन्होंने कहा कि इन ज्ञात–अज्ञात बलिदानियों की तपस्या इस गीत की हर पंक्ति में आज भी गूंजती है और हमें यह याद दिलाती है कि आज़ादी अटूट संकल्प और मातृभूमि के प्रति अनन्य प्रेम से अर्जित हुई है।

सभापति ने महान कवि सुब्रमण्य भारती की उस पंक्ति का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम् का स्वर दुनिया भर में तेजस्विता का प्रकाश फैलाता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् एक प्रण है – हमारी पहचान का, हमारी एकता का और हमारे सामूहिक भविष्य का। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले सभी वीरों को नमन करते हुए सभापति ने कहा कि उनका त्याग केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि राष्ट्र की अनंत प्रेरणा शक्ति है। उन्होंने कहा कि इस विशेष चर्चा का आरंभ करते हुए हमें तीन सूत्र याद रखने चाहिए—एकता हमारी शक्ति है, बलिदान हमारा मार्ग है, और भारत माता हमारी आत्मा है।

राधाकृष्णन ने सदन से आह्वान किया कि हम सब एक स्वर में संकल्प लें—ईमानदारी से राष्ट्र सेवा का, एकता के साथ आगे बढ़ने का और गर्व से उच्चारित करने का—वंदे मातरम्। वंदे मातरम्। वंदे मातरम्।

महाराष्ट्र: गुटखा तस्करों पर अंकुश के लिए मकोका कानून में किया जाएगा बदलाव : फडणवीस

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि सूबे में गुटखा तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका कानून) में बदलाव किया जाएगा। इससे राज्य में गुटखा, पान मसाला और चरस नशीले पदार्थ की खरीद फरोख्त पर लगाम लग सकेगी।

मुख्यमंत्री फडणवीस मंगलवार को नागपुर में चल रहे विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन में विधान सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस कानून मौजूदा वर्जन के तहत इसे लागू करने के लिए धमकी या शारीरिक नुकसान की जरूरत होती है, एक ऐसा प्रोविजन जो बैन प्रोडक्ट्स के आदतन वेंडर्स के खिलाफ इसका इस्तेमाल करना मुश्किल बनाता है। इसलिए राज्य सरकार ने केंद्रीय होम डिपार्टमेंट को इस कानून में बदलाव करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने कहा कि गुटखा और दूसरे तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट्स के लिए कई मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन मौजूदा कानून के चलते इस गैर-कानूनी व्यापार को रोकने में दिक्कत आ रही है।

मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि नशीले पदार्थों के ऑर्गनाइज्ड ट्रेडिंग नेटवर्क पर असरदार तरीके से नकेल कसने के लिए और मज़बूत कानूनी उपायों की जरूरत है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने नवी मुंबई, अहमदनगर, नागपुर, यवतमाल, नासिक, बुलढाणा और दूसरे शहरों नशीले पदार्थों पर कार्रवाई की गई है। मकोका कानून में अगर यह बदलाव लागू होता है, तो यह गैर-कानूनी गुटखा डिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ महाराष्ट्र की स्ट्रैटेजी में एक बड़ी बढ़त लाएगा, जिससे लंबे समय से एक रेगुलेटरी अपराध माना जाने वाला मामला एक ऑर्गनाइज्ड क्राइम का मामला बन जाएगा।

वीआईपी आगमन व विमान सुरक्षा को लेकर जयपुर में सख्त निर्देश

जयपुर। राजधानी जयपुर में वीआईपी एवं अति वीआईपी लोगों के प्रस्तावित आगमन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जयपुर शहर में व्यापक एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सुरक्षा कारणों से जहां शहर के कई इलाकों को ड्रोन रेड ज़ोन घोषित किया गया है,वहीं हवाई सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास लेजर लाइट के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार द्वारा जारी किया है कि सांगानेर, सांगानेर सदर, प्रतापनगर एवं जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा ड्रोन उड़ाने अथवा उसके उपयोग पर पूर्ण रोक रहेगी। इन क्षेत्रों को ड्रोन रेड ज़ोन घोषित करते हुए बिना अनुमति ड्रोन संचालन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह निर्णय वीआईपी मूवमेंट के दौरान संभावित सुरक्षा खतरों को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके साथ ही जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पांच किलोमीटर की परिधि में तथा आसपास स्थित सभी विवाह स्थल, होटल, बैंक्वेट हॉल एवं अन्य सार्वजनिक या निजी आयोजनों में दूर तक रोशनी देने वाली लेजर लाइट,आसमान में प्रकाशित होने वाले प्रकाश यंत्र अथवा किसी भी प्रकार के ऐसे ऑब्जेक्ट्स के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने लॉन्च किया जल शक्ति हैकथॉन और भारत-विन पोर्टल

नई दिल्ली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में 'जल शक्ति हैकथॉन–2025' और भारत-विन पोर्टल का उद्घाटन किया।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हैकथॉन में स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम, उद्योग, वैज्ञानिक, शिक्षण संस्थान, ग्रामीण और महिला युवा, निजी क्षेत्र और वैश्विक संस्थान भाग लेंगे। विजेताओं को प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट विकसित करने के लिए एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सीआर पाटिल ने श्रम शक्ति भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जल शक्ति हैकथॉन 2025 केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि यह पूरे देश में जल सुरक्षा, समावेशी और तकनीकी दृष्टिकोण से मजबूत जल भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन है। इस पहल के माध्यम से नागरिकों, शोधकर्ताओं, उद्योगों और नवप्रवर्तकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत-विन पोर्टल के जरिए जल क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। यह प्लेटफार्म खेतों में जल संरक्षण, ग्रामीण जल गुणवत्ता, स्मार्ट निगरानी, पारंपरिक जल प्रथाओं का पुनरुद्धार, बाढ़ और सूखा प्रबंधन जैसी जमीनी समस्याओं के व्यावहारिक, स्केलेबल और तैयार समाधान प्रस्तुत करेगा। हैकथॉन में जल संसाधन प्रबंधन, अपशिष्ट जल उपचार, जल उपयोग दक्षता, सर्कुलर अर्थव्यवस्था, जलवायु अनुकूलन, स्मार्ट जल ग्रिड, प्रिसिजन कृषि, वर्षा जल संचयन, नदी बेसिन और बाढ़ प्रबंधन तथा जलमापन मॉडलिंग जैसे विषय शामिल होंगे। इस हैकॉथन को राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी संस्थान, रुड़की कराएगी।

विदेशी आक्रांता हमारे आदर्श नहीं हो सकते: मुख्यमंत्री योगी

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन करने वाले लोग 'गुलामी की सोच' से ग्रस्त हैं और ऐसे हमलावर कभी भारत के आदर्श नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री ने यहां सैनिक स्कूल में भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर उनके नाम पर सभाकक्ष का उद्घाटन किया, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु के कुन्नूर में आठ दिसंबर 2021 को हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की मौत हो गई थी।

योगी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए 'पंच प्रण' की याद दिलाते हुए कहा, ''क्या कोई सच्चा भारतीय है जो एक कमजोर या गरीब भारत चाहेगा? हर सच्चा भारतीय एक सुरक्षित, विकसित और आत्मनिर्भर देश चाहता है।'' उन्होंने कहा, ''अगर हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं, तो ये पांच संकल्प हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने चाहिए।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि पहला संकल्प अपनी विरासत पर गर्व करने का है। उन्होंने कहा, ''हमें भगवान राम, भगवान कृष्ण, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी और रानी लक्ष्मीबाई की विरासत पर गर्व है। जो समाज अपने नायकों को भूलता है, वह आगे नहीं बढ़ सकता।'' योगी ने कहा कि दूसरा संकल्प गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह त्यागने का है। उन्होंने कहा, ''कुछ लोगों को लगता है कि विदेशी चीजें बेहतर और भारतीय चीजें कमतर हैं। यही गुलामी की सोच है।'' मुख्यमंत्री ने पूछा, ''हमें सिकंदर को महान क्यों कहना चाहिए? महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोबिंद सिंह जी, पृथ्वीराज चौहान या जनरल बिपिन रावत को क्यों नहीं?'' उन्होंने कहा, ''हमारे नायक, हमारे बहादुर सैनिक और परमवीर चक्र विजेता हैं। विदेशी हमलावर हमारे लिए कभी महान या आदर्श नहीं हो सकते।''

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय उपलब्धियों की कीमत पर विदेशी विचारों की प्रशंसा करना 'कॉलोनियल सोच' है और इसे खत्म करना होगा। योगी ने तीसरे संकल्प 'सुरक्षा बलों का सम्मान' का जिक्र करते हुए कहा कि सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल देश की सुरक्षा के लिए निरंतर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति की गलती से पूरा संस्थान गलत नहीं हो जाता। मुख्यमंत्री ने चौथे संकल्प 'सामाजिक एकता' पर बल देते हुए कहा कि जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर समाज को बांटने की कोशिशें देश के लिए हानिकारक हैं। बिना किसी का नाम लिये विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांटते हैं और सत्ता में आने पर सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। योगी ने कहा, ''भारत की तरक्की एकता में है। जिसे भारतीय होने पर गर्व नहीं, उसे खुद विचार करना चाहिए।'' पांचवें संकल्प का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारों की लड़ाई में उलझा देश तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, ''हमें छोटे-मोटे हितों से ऊपर उठकर कर्तव्य भावना से काम करना चाहिए।''

मुख्यमंत्री योग ने कहा कि जनरल बिपिन रावत राष्ट्रगौरव, कर्तव्य और साहस के प्रतीक थे, और उनके नाम पर बना सभाकक्ष व स्थापित प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी।

कार्रवाई घुसपैठियों पर लेकिन दर्द सपा-कांग्रेस को हो रहा: डिप्टी सीएम

उन्नाव। उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने आज कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लाल टोपी वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश के वर्ष 27 के विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी। अभी मतदाता शुद्धिकरण अभियान में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस वालों को दर्द हो रहा है। गत लोकसभा चुनाव में भी मोदी को प्रधानमंत्री न बनने देने को लेकर इन्हीं दलों ने दुष्प्रचार किया था। सच कहूं तो यह सब देश के दुश्मन हैं।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज उन्नाव जिले में जिला भाजपा मुख्यालय पर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विपक्षी दलों पर करारा हमला करते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने गत लोकसभा चुनावों में दुष्प्रचार किया था कि भाजपा सत्ता में आई तो संविधान और आरक्षण खत्म कर देगी, लेकिन यह दुष्प्रचार भी इनके काम नहीं आया क्योंकि यह सब लोकतंत्र के दुश्मन है। भाजपा ने कार्यकर्ताओं के बल पर दिल्ली में दो तिहाई बहुमत से रेखा गुप्ता की सरकार बनी है। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीतकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाई है। बिहार की इस बड़ी जीत का कारण के कारण पश्चिम बंगाल की तृण मूल कांग्रेस सरकार बौखला गई है। मौर्य कहा कि हमारी सरकार घुसपैठियों पर कार्यवाही करती है तो दर्द सपा प्रमुख अखिलेश को होता है। उन्होंने कहा कि सिमी के कई आतंकियों पर कार्रवाई हुई थी लेकिन अखिलेश सरकार ने मुकदमे वापस लिए थे जबकि कई को न्यायालय ने फांसी तक की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं सपा सरकार ने ही अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थीं। उन्होंने आगे कहा कि उन्नाव क्रांतिवीरों की धरती है।

वंदे मातरम का 150 वर्ष हो गया है। अनेकों क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम का जय घोष कर अपना जीवन राष्ट्र के लिए बलिदान किया है लेकिन विपक्षी दल इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मोदी प्रधानमंत्री न बनते तो राम मंदिर निर्माण और धारा 370 हटना संभव नहीं था। कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री मौर्य ने सदर विधानसभा के गांव टीकर गढ़ी में सेक्टर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक क। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के संदर्भ में बात की। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी की अगुवाई में उप मुख्यमंत्री का कानपुर रोड पर बनी पुल, सोहरामऊ नवाबगंज, दही चौकी में पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्टी की जनपद प्रभारी अर्चना मिश्रा, पंकज गुप्ता,, बृजेश रावत, अनिल सिंह, बम्बा लाल दिवाकर, रामचंद्र प्रधान सदस्य विधान परिषद, श्रीकांत कटियार सहित सभी विधायक, जिला पंचायत शकुन सिंह उपस्थित रहे। इनके अतिरिक्त जनपद के सभी मंडल अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पूर्व जिला अध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में भागीदारी की

50 हजार का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर, सिपाही घायल

शामली। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में थानाभवन क्षेत्र व बाबरी पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश मारा गया। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान राज्यों के कई थानों में 28 मुकदमें दर्ज थे। इस कार्रवाई में एक पुलिस का सिपाही भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने मंगलवार को बताया कि मुठभेड़ में ढेर बदमाश की पहचान शामली जिले के मोहल्ला रायजादगान निवासी समयदीन उर्फ सामा के रूप में पहचान हुई है। उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। एसपी ने बताया कि देर रात को थानाभवन को सूचना मिली कि इनामी बदमाश साथियों संग ग्राम भैंसानी ईस्लामपुर में बन्द पड़े ईंट के भट्टे में छिपा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी बिजेन्द्र सिंह रावत और थाना प्रभारी बाबरी राहुल सिसौदिया फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली बाबरी थाना प्रभारी राहुल के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी तो वहीं दूसरी गोली लगने से सिपाही अनुज यादव घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश समयदीन घायल हो गया।

बदमाश और सिपाही को घायल हालत में इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया गया, जहां से जिला अस्पताल शामली रेफर कर दिया गया। जहां डॉक्टरों ने इनामी बदमाश को इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया, जबकि सिपाही अनुज का इलाज चल रहा है। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश के पास से पुलिस को 9 एमएम और 32 बोर की पिस्टल समेत कारतूस बरामद हुए हैं। एसपी ने बताया कि बदमाश समयदीन उर्फ सामा शातिर किस्म का बदमाश था तथा थाना कांधला का हिस्ट्रीशीटर अपराधी था।

वह अपने गिरोह के साथ घटना कारित करने के लिये आता था। उसके खिलाफ डकैती, लूट, चोरी आदि के कुल 28 अभियोग जनपद शामली, सहारनपुर, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान के जयपुर में दर्ज हैं। मुठभेड़ की इस कार्रवाई के दौरान मारे गए बदमाश के अन्य साथी अंधेरे में फरार हो गये हैं, जिनकी तलाश के लिए काम्बिंग की जा रही है।

प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने के आरोप में तीन लोग गिरफ्तार

कन्नौज। जिले के ठठिया क्षेत्र में पुलिस ने बहला-फुसला कर एवं प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि सोमवार को पार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें अन्नू बाबू, विद्या सागर और उमा शंकर दोहरे के खिलाफ करसाह गांव में बने चर्च में हिंदू धर्म के कुछ लोगों को बहला-फुसला कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने बताया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम,2021 के तहत तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें सोमवार रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया। कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा चर्च की तलाशी के दौरान वहां बाइबल की 20 प्रतियां, ईसाई धर्म से जुड़े लॉकेट और अंगूर के रस की बोतल बरामद की गई है।

गांधी-नेहरू परिवार आज भी राजा की तरह करता है व्यवहार : ब्रजेश पाठक

रायबरेली। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गांधी परिवार पर जमकर हमला किया। मंगलवार को रायबरेली में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेहरू-गांधी परिवार राजा की तरह व्यवहार करता है और अब भी खुद को सत्ता में मानता है। पाठक ने संसद में दिए प्रियंका गांधी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का दिया बयान यह बताता है कि गांधी परिवार आज भी अपने आपको सत्ता में मानता है। इसलिए ही वे राजा की तरह व्यवहार करते हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश में बंटवारे की जिम्मेदार नेहरू-गांधी परिवार ही है। उन्होंने दावा किया कि अब जनता ने गांधी परिवार को नकार दिया है।

मीडिया के कफ सिरप मामले के सवाल पर उप मुख्यमंत्री पाठक ने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। इससे पूर्व जनपद आगमन पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा कार्यालय अटल भवन में संगठनात्मक कार्यों के साथ एसआईआर अभियान की समीक्षा की।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इसलिए परेशान है कि अवैध घुसपैठियों का नाम कट रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी घुसपैठिया मतदाता सूची में न रहे, यह हमारी प्राथमिकता है।

कॉलेज में नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों से 15 लाख की ठगी

बांदा। नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से 15 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ितों की तहरीर पर मंगलवार को थाना मटौंध पुलिस ने आरोपित विनोद कुमार पुत्र बाबू यादव निवासी ग्राम अछरौंड के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मटौंध थाना प्रभारी संदीप कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत जवाहर नगर निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र रमेश व उसके साथी हीरू पुत्र राकेश कुमार ने तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि फरवरी 2025 में उनकी मुलाकात विनोद कुमार से हुई थी। विनोद ने स्वयं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ा प्रभावशाली व्यक्ति बताते हुए बांदा व चित्रकूट के इंटर कॉलेजों में "क्लर्क" के दो पद खाली होने की बात कही और उनकी नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया।

उसके विश्वास में आने पर दोनों ने 15 लाख रुपये की बड़ी रकम उसके बताए खातों में ट्रांसफर कर दी। पीड़ितों के अनुसार, विनोद कुमार ने सितंबर माह में दोनों को नियुक्ति पत्र सौंपे और कहा कि वे राजकीय इंटर कॉलेज बांदा व राजकीय इंटर कॉलेज चित्रकूट में जाकर ज्वॉइन कर लें। लेकिन जब दोनों कॉलेजों में पता किया गया तो यह खुलासा हुआ कि ऐसी कोई नियुक्ति निकली ही नहीं थी और न ही कोई पद खाली था। नियुक्ति पत्र पूरी तरह फर्जी पाए गए।

मामले की जानकारी पर जब उन्होंने पैसे वापस मांगें तो आरोपित विनोद कुमार कथित रूप से गाली-गलौज करने के साथ ही जान से मारने की धमकियां देने लगा। इस ठगी मामले में आरोपित ने खुद के खाता में 11 लाख, अपने पिता के खाते में 1.50 लाख, सूरज भान यादव और विक्रम कश्यप के खाते में 1-1 लाख व मोहम्मद अख्तर के खाते में 50 हजार रुपये डलवाए हैं। इस तहरीर पर मटौंध थाना में आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी एवं संगठित ठगी से संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है और संबंधित खातों की लेन-देन की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

सड़क हादसे में मिर्जापुर में तैनात आरक्षी की मौत

बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मिर्जापुर में तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षी की मौत हो गई। दुर्घटना बांदा शहर कोतवाली अंतर्गत सर्वोदय नगर मोहल्ले के मुख्य मार्ग पर टेस्ला ऑटो मोबाइल के सामने हुई।

मृतक के भाई दीपक गुप्ता पुत्र लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम ठेड़ा, थाना सुमेरपुर, जिला हमीरपुर के शहर कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि मेरा छोटा भाई कन्हैया गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर जनपद मिर्जापुर के पुलिस ऑफिस में तैनात था, सोमवार 8 दिसंबर 2025 को अपनी ड्यूटी पर वापस लौटने वाला था। लेकिन अचानक पिता की तबीयत खराब हो जाने के कारण वह समय से रवाना नहीं हो सका और इलाज के लिए घर रहना पड़ा। रात्रि में ट्रेन पकड़ने के लिए वह मोटरसाइकिल से बांदा आया था। शाम करीब 4.30 बजे सर्वोदय नगर के मुख्य मार्ग पर पहुंचते ही टैम्पो संख्या UP 90 AT 7956 के अज्ञात चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए कन्हैया की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उसके हाथ, पैर व शरीर पर गंभीर चोटें आईं।सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच कर मित्रों की मदद से घायल आरक्षी को जिला अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे कानपुर रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। शहर कोतवाली प्रभारी बलराम सिंह ने मंगलवार को बताया कि तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

सड़क हादसे में घायल दारोगा का लखनऊ में निधन

बहराइच। जनपद में ड्यूटी जाते समय सड़क हादसे में घायल हुए जालिमनगर पुलिस चौकी में तैनात दारोगा राहुल गुप्ता की मंगलवार सुबह लखनऊ में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। खबर मिलते ही परिजन और पुलिस महकमे के लोग शोकाकुल हो उठे। बहराइच जिले के थाना मोतीपुर की जालिमनगर पुलिस चौकी में तैनात दारोगा राहुल गुप्ता सोमवार शाम लगभग पांच बजे सड़क हादसे में घायल हुए थे। वह ड्यूटी से लौटते समय गूढ़ चौराहे के पास बाइक से जा रहे थे कि अचानक एक वाहन के सामने आ जाने से बाइक का संतुलन बिगड़ने से हादसे का शिकार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वाहन की टक्कर लगने से दारोगा राहुल सड़क पर गिर पड़े और उन्हें सिर में काफी गंभीर चोटें आईं। उन्हें तत्काल सीएचसी ले जाया गया, लेकिन स्थिति को देखते हुए घायल दारोगा को बहराइच मेडिकल कालेज लाया गया। लेकिन यहां भी जब सुधार होता नहीं दिखा तो फिर उन्हें देर रात लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। मंगलवार सुबह इलाज के दौरान दारोगा राहुल गुप्ता ने दम तोड़ दिया। उनके निधन का समाचार मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई।

अन्तरजनपदीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के 3 अपराधी गिरफ्तार 80 लाख की हेरोइन जब्त

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की जफराबाद पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मंगलवार को अन्तरजनपदीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 400 ग्राम हेरोइन बरामद की हैं, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 80 लाख रुपये है। एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि जफराबाद पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मंगलवार दोपहर बेलाव घाट पुल पर वाहन चेकिंग के दौरान इन तस्करों को पकड़ा। इनकी पहचान गाजीपुर के बड़हरा निवासी राकेश यादव, सिकंदर यादव और जौनपुर के नंदगांव निवासी आकाश चौहान के रूप में हुई हैं। ये तीनों गाजीपुर से जौनपुर के लिए एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल से हेरोइन की तस्करी कर रहे थे। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि मादक पदार्थ को गाजीपुर से खरीदकर लाते हैं। यहां पर उसे ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। कुछ खास व्यक्तियों को भी इसकी आपूर्ति करते थे। पुलिस को इनके पास से हेरोइन के अलावा एक डिजिटल तराजू, सात मोबाइल फोन और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अभियुक्तों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई।

महिला सिपाही ने अपने पुलिसकर्मी पति समेत ससुराल के छह लोगों पर दर्ज कराया मुकदमा

पीलीभीत। जिले की बीसलपुर कोतवाली में तैनात एक महिला सिपाही ने अपने सिपाही पति सहित ससुराल के छह लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि महिला आरक्षी ने गत रविवार को पंजीकृत कराए गए मुकदमे में कहा है कि उसके पिता ने उसका विवाह 26 जनवरी 2023 को मेरठ जिले के खरखौदा इलाके के निवासी प्रियंक शर्मा से किया था।

प्रियंक भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। उन्होंने बताया कि महिला आरक्षी का आरोप है कि विवाह में उसके पिता ने भरपूर दहेज और एक चार पहिया गाड़ी भी दी थी, लेकिन उसके ससुराल के लोग और दहेज की मांग कर रहे हैं। शिकायत के मुताबिक, पति प्रियंक शर्मा, सास कुंती देवी, ससुर राजेश्वर प्रसाद, जेठ अनुज शर्मा, उसकी पत्नी श्वेता, जेठ मुकेश तथा उसकी पत्नी संतोष अक्सर पीड़िता को परेशान करते और मारते-पीटते थे। सूत्रों ने बताया कि महिला आरक्षी का आरोप है कि पिछले साल पांच सितंबर को उसने अपने पति प्रियंक शर्मा को अपनी एक जेठानी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और उसका विरोध किया था।

उन्होंने बताया कि महिला कांस्टेबल की तहरीर पर बीसलपुर कोतवाली में सभी नामजद आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना), 351(3) (आपराधिक धमकी) और दहेज निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है।

ललित कला की 7 दिवसीय कार्यशाला में भारतीय कला परम्परा को सुदृढ़ करने में जुटे छात्र

अयोध्या। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के मूर्ति कला विभाग में 07 दिवसीय भित्ति चित्र एवं मूर्तिकला कार्यशाला का निरीक्षण कुलपति कर्नल डॉ. बिजेंद्र सिंह द्वारा किया गया।

कुलपति ने कार्यशाला की प्रशंसा करते हुए छात्र - छात्राओं को प्रोत्साहित किया तथा कहा कि ललित कला विभाग को विश्वविद्यालय का सबसे सुन्दर एवं आकर्षक विभाग बनाने का कार्य पूरी लगन से किया जाएगा। ललित कला के समन्वयक प्रो. सुरेंद्र मिश्रा ने कार्यशाला के कार्य में यथासंभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

कार्यशाला की संयोजक डॉ. सरिता द्विवेदी ने बताया कि भित्ति चित्रण में अवध के कुम्हारों के चित्र को 3 डी में बनाया जा रहा है। भारतीय कला परम्परा को बढ़ाने का कार्य ललित कला द्वारा हो रहा है। कार्यशाला की आयोजन सचिव डॉ. रीमा सिंह ने बताया की विभागीय परिसर में विभिन्न कलात्मक संस्थापन कलाकृतियों को स्थापित किया जायेगा, जो आगंतुकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेंगी।

इस अवसर पर प्रो. आशुतोष सिंहा, एस. एस. मिश्र, प्रो. फारुख जमाल, प्रो. मृदुला मिश्रा, प्रो. विनोद कुमार श्रीवास्तव, प्रो. प्रिया कुमारी, डॉ. अलका श्रीवास्तव, डॉ. सरिता सिंह छात्र -छात्राओं में वरुण, हर्षिता, प्राची, व्यू, साक्षी, अदिति, कृष्णा के साथ कर्मचारीगण मौजूद रहे।

युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

उरई। उरई कोतवाली क्षेत्र के कांशीराम कॉलोनी में मंगलवार को एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेजकर मामले की जांच में जुट गई।

कांशीराम कालोनी में किराये के कमरे में रहने वाला नेपाली वर्मा (45) शराब का आदी था। मंगलवार को उसके कमरे से तेज दुर्गंध आ रही थी।पड़ोसियों ने किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका होने पर पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर पहुंची पुलिस ने नेपाली वर्मा का शव फांसी के फंदे से लटका देखा। पुलिस ने फोरेंसिक टीम संग घटनास्थल की जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। कोतवाल हरिशंकर ने बताया कि पड़ोसियों पूछने पर पता चला है कि नेपाली वर्मा शराब का लती थी। दो दिन से वह किसी को नहीं दिखा। दरवाजा भी बंद था। कमरे की छानबीन के दौरान कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामला संदिग्ध है, इसलिए सभी एंगल से जांच की जा रही है।

मायके में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव

प्रयागराज। हंडिया थाना क्षेत्र में मंगलवार को विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि हंडिया थाने को सूचना मिली की असवां दाउदपुर गांव में अपने मायके में रह रही सुषमा देवी (22) पत्नी दीपक ने घर के अन्दर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर पहुंची थाना पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों से पूछताछ की। परिवारीजनों का कहना है कि सुषमा चार बहनों में तीसरे नंबर की थी। उसकी शादी इस वर्ष 5 जून को हंडिया थाना क्षेत्र के भीटी गांव निवासी दीपक के साथ हुई थी। हालांकि वर्तमान में वह अपने मायके में रह रही थी। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि महिला की मौत का कारण स्पष्ट न होने की वजह से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

आईपीएल 2026 की नीलामी में 240 भारतीयों सहित 350 खिलाड़ी शामिल

मुंबई। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की 16 दिसंबर को अबुधाबी में होने वाली नीलामी में कुल 350 क्रिकेटरों की बोली लगेगी जिनमें 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। हाल ही में वनडे में संन्यास से वापसी करने वाले दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक का नाम भी अंतिम सूची में शामिल किया गया है। उनका आधार मूल्य एक करोड़ रुपये है। इस सूची में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी शामिल हैं, जिनका आधार मूल्य दो करोड़ रुपये है। स्मिथ आखिरी बार 2021 में आईपीएल में खेले थे।

आईपीएल की एक विज्ञप्ति के अनुसार खिलाड़ियों की नीलामी के लिए कुल 1390 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था। इसे बाद में घटाकर 1005 पर दिया गया था। इन खिलाड़ियों में से ही अंतिम 350 खिलाड़ियों की सूची तैयार की गई है। आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजी टीमें इन 350 खिलाड़ियों में से ही बाकी बचे 77 स्थान को भरेंगे। नीलामी में खिलाड़ियों के पहले सेट में भारत और मुंबई के बल्लेबाज पृथ्वी साव और सरफराज खान शामिल हैं। इन दोनों ने अपना आधार मूल्य 75 लाख रुपये रखा है। साव 2018 से 2024 तक आईपीएल में खेले थे, लेकिन पिछली बार नीलामी में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था। सरफ़राज 2021 के बाद से इस प्रतियोगिता में नहीं खेले हैं।

आईपीएल द्वारा साझा की गई सूची में दो आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरन ग्रीन और जेक फ्रेजर मैकगर्क के अलावा न्यूजीलैंड और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे और दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर भी शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक का आधार मूल्य दो करोड़ रुपये है। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) द्वारा रिलीज किए गए ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर ने अपना आधार मूल्य दो करोड़ रुपये रखा है। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले कुणाल चंदेला और अशोक कुमार भी नीलामी की अंतिम सूची में शामिल हैं। तीन बार की विजेता केकेआर 64.3 करोड़ रुपये की सबसे अधिक धनराशि के साथ नीलामी में उतरेगी। उसके बाद पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का नंबर आता है जिसके पास 43.4 करोड़ रुपये की धनराशि बची है। एक बार आईपीएल खिताब जीत चुकी सनराइजर्स हैदराबाद 25.5 करोड़ रुपये के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर है। नीलामी की अंतिम सूची में इंग्लैंड के 21 खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ, तेज गेंदबाज गस एटकिंसन, लियाम लिविंगस्टोन और टेस्ट सलामी बल्लेबाज बेन डकेट शामिल हैं।

इस नीलामी में ग्रीन पर बड़ी बोली लगने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया के कुल 19 खिलाड़ी सूची में शामिल हैं। इनमें ग्रीन के अलावा जोश इंगलिस, मैथ्यू शॉर्ट, कूपर कोनोली और ब्यू वेबस्टर अन्य प्रमुख नाम हैं। दक्षिण अफ्रीका के 15 खिलाड़ी नीलामी सूची का हिस्सा हैं। इनमें डिकॉक और मिलर के साथ तेज गेंदबाज एनरिक नोर्किया, लुंगी एनगिडी, गेराल्ड कोएट्जी और ऑलराउंडर वियान मुल्डर भी शामिल हैं। नीलामी की सूची में जगह बनाने वाले वेस्टइंडीज के नौ खिलाड़ियों में तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ और शमर जोसेफ, एकीम ऑगस्टे, शाई होप और रोस्टन चेस शामिल हैं।

श्रीलंका के जिन 12 खिलाड़ियों ने नीलामी सूची में जगह बनाई है उनमें वानिंदु हसरंगा, दुनीथ वेल्लालेज, महेश तीक्षाना, त्रवीन मैथ्यू, पथुम निसांका, कुसल मेंडिस और कुसल परेरा भी शामिल है। न्यूजीलैंड के 16 और अफगानिस्तान के 10 खिलाड़ियों को नीलामी सूची में जगह मिली है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों में रचिन रवींद्र भी शामिल हैं जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने रिलीज कर दिया था। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों में रहमानुल्लाह गुरबाज और नवीन उल हक भी शामिल हैं।

- हाल ही में वनडे में संन्यास से वापसी करने वाले दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक का नाम भी अंतिम सूची में शामिल किया गया है। उनका आधार मूल्य एक करोड़ रुपये है। इस सूची में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी शामिल हैं, जिनका आधार मूल्य दो करोड़ रुपये है। स्मिथ आखिरी बार 2021 में आईपीएल में खेले थे।
- आईपीएल की एक विज्ञप्ति के अनुसार खिलाड़ियों की नीलामी के लिए कुल 1390 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था। इसे बाद में घटाकर 1005 पर दिया गया था। इन खिलाड़ियों में से ही अंतिम 350 खिलाड़ियों की सूची तैयार की गई है। आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजी टीमें इन 350 खिलाड़ियों में से ही बाकी बचे 77 स्थान को भरेंगे।

दबाव से पार पाकर नौ साल बाद जूनियर हॉकी विश्व कप में पदक जीतने के इरादे से उतरेगा भारत

चेन्नई। जर्मनी के हाथों करारी हार के साथ खिताब का सपना टूटने के बाद भारतीय टीम जूनियर हॉकी विश्व कप के कांस्य पदक के मुकाबले के लिये बुधवार को अर्जेंटीना के खिलाफ उतरेगी तो नौ साल बाद पदक जीतने के लिये उसे दबाव में गलतियां करने की आदत से पार पाना होगा । पिछले दो विश्व कप में चौथे स्थान पर रही भारतीय टीम को उन गलतियों को दोहराने से बचना होगा जो उसने सेमीफाइनल में सात बार की चैम्पियन जर्मनी के खिलाफ की और 1-5 से पराजय झेलनी पड़ी । भुवनेश्वर में 2021 में और कुआलालम्पुर में 2023 में हुए जूनियर विश्व कप में भारत क्रमशः फ्रांस और स्पेन से 3-1 से हारकर चौथे स्थान पर रहा था ।

होबर्ट में 2001 के बाद भारत ने दूसरा और आखिरी खिताब 2016 में लखनऊ में जीता था । तोक्यो और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुके भारतीय टीम के मुख्य कोच पी आर श्रीजेश को बखूबी पता है कि यह पदक उनकी टीम के लिये कितना जरूरी है लेकिन उन्हें यह भी अहसास है कि सेमीफाइनल में स्पेन के खिलाफ आखिरी मिनटों में गोल गंवाकर 1-2 से हारी अर्जेंटीना की चुनौती को कमतर नहीं आंका जा सकता । दो बार की चैम्पियन अर्जेंटीना ने 2021 में फाइनल में जर्मनी को 4-2 से हराकर खिताब जीता था । कोच श्रीजेश ने कहा था,'' हमें अपने खेल पर नियंत्रण रखना सीखना होगा और बड़ी टीमों को इतने मौके देने से बचना होगा । विरोधी टीम के अच्छा खेलने पर दबाव में आकर हम अपने बेसिक्स ही भूल जाते हैं जिससे उबरना होगा । गोल करने के मौके बनाना और तब्दील करना जरूरी है । छोटी छोटी गलतियां ही भारी पड़ रही हैं जिनसे बचना होगा। दूसरी ओर अर्जेंटीना टीम अपने पूल में तीन में से दो मैच जीतकर शीर्ष पर रही थी और क्वार्टर फाइनल में उसने नीदरलैंड को एक गोल से हराया।

टूर्नामेंट से पहले भारत और अर्जेंटीना ने तीन अभ्यास मैच मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम पर ही खेले थे जिसमे पहला 1-1 से ड्रॉ रहा, दूसरा भारत ने 5-3 से और तीसरा अर्जेंटीना ने 2-1 से अपने नाम किया था । अर्जेंटीना के कोरिया ब्रूनो टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं और छह गोल कर चुके हैं।

कोलकाता दौड़ में ओलंपिक और विश्व चैंपियन सहित 23000 धावक भाग लेंगे

कोलकाता। दो बार के ओलंपिक और तीन बार के विश्व चैंपियन जोशुआ चेप्टेगी सहित दुनिया भर के 23000 से अधिक धावक 21 दिसंबर को यहां होने वाली 10वीं टाटा स्टील वर्ल्ड 25के (25 किलोमीटर) कोलकाता दौड़ में भाग लेंगे। युगांडा के चेप्टेगी और महिला वर्ग में गत चैंपियन सुतूम असेफा केबेडे इस दौड़ का मुख्य आकर्षण होंगे जिसे विश्व एथलेटिक्स की तरफ से गोल्ड लेबल रोड रेस का दर्जा हासिल है।

प्रमोटर प्रोकैम इंटरनेशनल ने भी इस बार 1:11:08 (एक घंटा, 11 मिनट, 08 सेकंड) का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाले किसी भी एथलीट को 25,000 अमेरिकी डॉलर का बोनस देने की घोषणा की है। इस दौड़ की कुल पुरस्कार राशि 142,214 डॉलर है, जिसमें पुरुष और महिला वर्ग के विजेताओं के लिए बराबर की पुरस्कार राशि रखी गई है। शीर्ष तीन स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 15,000 डॉलर, 10,000 डॉलर और 7,000 डॉलर का इनाम मिलेगा। प्रतियोगिता का नया रिकार्ड बनाने वाले खिलाड़ियों को 5,000 डॉलर का अतिरिक्त बोनस भी मिलेगा। चेप्टेगी (29 वर्ष) ने 10,000 मीटर में लगातार तीन विश्व खिताब जीते हैं और उनके नाम चार विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं। पिछले वर्ष दिल्ली हाफ मैराथन और इस वर्ष बेंगलुरु में आयोजित टीसीएस वर्ल्ड 10के (10किमी) के विजेता चेप्टेगी के नाम पर अब भी 5000 किमी और 10000 किमी के विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं। पुरुषों की सूची में एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी तंजानिया के अल्फोंस फेलिक्स सिम्बू भी शामिल हैं। महिला वर्ग में इथियोपिया की स्टार सुतूम असेफा केबेडे ने पहली बार 2015 में बर्लिन में 25 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया था।

पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास आयोजित मैराथन में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया

मेंढर/जम्मू। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी के पास सेना द्वारा आयोजित की गई मैराथन में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। भीमबेर गली ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर राहुल कुमार ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई और युवाओं को फिटनेस को जीवन शैली के रूप में अपनाने और सशस्त्र बलों में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रेरित किया। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि यह मैराथन दूसरी बार आयोजित किया जा रहे मेंढर महोत्सव का हिस्सा थी। यह महोत्सव 23 नवंबर को शुरू हुआ और 11 दिसंबर को समाप्त होगा। अधिकारी ने बताया कि चुनौतीपूर्ण भूभाग और संवेदनशील स्थान होने के बावजूद इस मैराथन में 1,500 से अधिक धावकों ने भाग लिया।

हेजलवुड एशेज से बाहर, कमिंस की ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी तय

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड घुटने की चोट के कारण एशेज से बाहर

ब्रिस्बेन। एशेज श्रृंखला के पहले दो मैच गंवाने वाली इंग्लैंड की टीम को एडिलेड में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच से पहले मंगलवार को यहां तब करारा झटका लगा जब उसके तेज गेंदबाज मार्क वुड चोटिल होने के कारण इस श्रृंखला से बाहर हो गए। वुड पर्थ में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच में खेले थे लेकिन अपना खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे। उन्होंने 11 ओवर किए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। वह बाएं घुटने में तकलीफ़ के कारण वे ब्रिस्बेन में दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाए थे। इस 35 वर्षीय खिलाड़ी की फिटनेस एशेज श्रृंखला से पहले एक मुद्दा बनी थी क्योंकि मार्च में घुटने की सर्जरी के बाद उन्होंने हाल में वापसी की थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2022 में अपना एकमात्र टेस्ट मैच खेलने वाले मैट फिशर को कवर के रूप में टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। वुड ने इंस्टाग्राम पर जारी की गई पोस्ट में कहा, ''मैं एशेज से बाहर होने से बहुत दुखी हैं। टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए सर्जरी और सात महीनों की कड़ी मेहनत और रिहैबिलिटेशन के बावजूद मेरा घुटना अब तक ठीक नहीं हो पाया है।'' इंग्लैंड को एशेज जीतने की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखने के लिए 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होने वाला तीसरा टेस्ट हर हाल में जीतना होगा। इंग्लैंड ने 2010-11 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट नहीं जीता है और वुड के बाहर होने से उसका गेंदबाजी आक्रमण कमजोर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड भी चोटिल होने के कारण श्रृंखला से बाहर हो गए हैं।

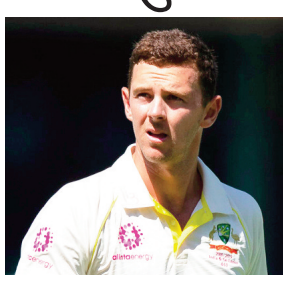

ब्रिस्बेन। आस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड हैमस्ट्रिंग और टखने की चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ एशेज श्रृंखला के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए हैं लेकिन कप्तान पैट कमिंस पीठ की समस्या से उबरकर वापसी करने के लिए तैयार हैं।

हेजलवुड चोटिल होने के कारण पर्थ और ब्रिस्बेन में खेले गए पहले दो मैच में भी नहीं खेल पाए थे लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि वह पांच मैचों की श्रृंखला के बाकी मैच में वापसी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया पहले दो मैच जीतकर श्रृंखला में 2-0 से आगे है। आस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने मंगलवार को कहा कि हेजलवुड अब अगले साल की शुरुआत में होने वाले टी20 विश्व कप में वापसी करने का लक्ष्य रखेंगे।

मैकडोनाल्ड ने कहा, ''वह एशेज श्रृंखला से बाहर रहेंगे और विश्व कप के लिए तैयारी करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह उनके लिए वास्तव में निराशाजनक है कि वह इस श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। यह ऐसा झटका है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हमें उनसे इस श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद थी।'' इस बीच कमिंस के 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट में वापसी करने की उम्मीद है। पीठ की समस्या के कारण वह पहले दो टेस्ट मैचों में नहीं खेल पाए थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के खिलाफ गाबा में जब दूसरा टेस्ट मैच खेल रही थी तब इस 32 वर्षीय तेज गेंदबाज ने ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में कड़ा अभ्यास किया था। तीसरे टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम की घोषणा बुधवार को की जाएगी जिसमें कमिंस की कप्तान के रूप में वापसी तय है।

कमिंस की अनुपस्थिति में स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई टीम की अगुवाई कर रहे हैं। मैकडोनाल्ड ने कहा, ''हमें लगता है कि वह पूरी तरह से तैयार होंगे। उन्होंने जिस तरह से अभ्यास किया है उसे देखकर हमें लगता है कि वह एडिलेड की चुनौतियों के लिए वास्तव में अच्छी स्थिति में होंगे।'' चौथा टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर बॉक्सिंग डे (26 दिसंबर) से शुरू होगा और सिडनी चार जनवरी से पांचवें टेस्ट की मेजबानी करेगा। इंग्लैंड ने 2010-11 की श्रृंखला के बाद से ऑस्ट्रेलिया में कोई एशेज टेस्ट नहीं जीता है।

सरकारी समिति ने एआई कंपनियों को कॉपीराइट कार्यों के उपयोग के लिए व्यापक लाइसेंस का दिया सुझाव

नई दिल्ली। कृत्रिम मेधा (एआई) डेवलपर को एआई प्रणालियां तैयार करने के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध सभी कॉपीराइट-संरक्षित सामग्री का उपयोग करने के लिए अनिवार्य लाइसेंस देने का एक सरकारी समिति ने सुझाव दिया है। साथ ही इस पर संबंधित हितधारकों से प्रतिक्रिया व विचार मांगे गए हैं। समिति की सिफारिश के अनुसार, लाइसेंस के साथ कॉपीराइट धारकों के लिए वैधानिक पारिश्रमिक का अधिकार भी होना चाहिए। ये सुझाव समिति द्वारा तैयार किए गए कार्य पत्र का हिस्सा हैं जिसे उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा हितधारकों के विचार जानने के लिए जारी किया गया है। एआई प्रणालियों और कॉपीराइट से संबंधित उभरते मुद्दों पर विचार-विमर्श की बढ़ती आवश्यकता को स्वीकार करते हुए डीपीआईआईटी ने 28 अप्रैल 2025 को एक समिति का गठन किया था। आठ सदस्यीय इस समिति की अध्यक्षता अतिरिक्त सचिव हिमानी पांडे ने की।

इसमें कानूनी विशेषज्ञ, उद्योग और शिक्षा जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इसे समिति को एआई प्रणालियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की पहचान करने, मौजूदा नियामक ढांचे की जांच करने, इसकी पर्याप्तता का आकलन करने और यदि आवश्यक हो तो बदलावों की सिफारिश करने के अलावा हितधारकों के साथ परामर्श के लिए एक कार्य पत्र तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। समिति ने कार्य पत्र (भाग-1) तैयार किया है जिसे डीपीआईआईटी द्वारा आठ दिसंबर को सार्वजनिक रूप से जारी किया गया। इसने 30 दिन के भीतर सभी संबंधित हितधारकों से प्रतिक्रिया और विचार मांगे हैं।

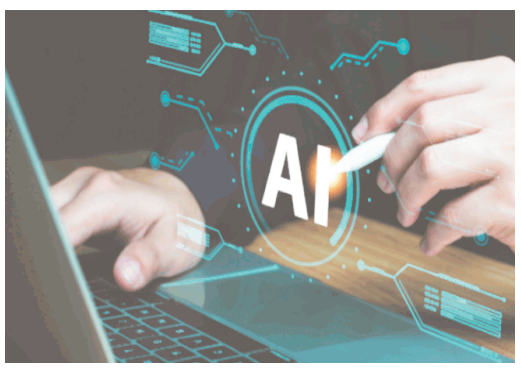

पत्र में कहा गया, '' बहुमत के आधार पर समिति ने एआई प्रणाली के प्रशिक्षण में सभी वैध रूप से प्राप्त कॉपीराइट-संरक्षित कार्यों के उपयोग के लिए एआई डेवलपर के पक्ष में एक अनिवार्य व्यापक लाइसेंस की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। साथ ही कॉपीराइट धारकों के लिए एक वैधानिक पारिश्रमिक अधिकार भी दिया गया है।'' इस ढांचे के तहत, अधिकार धारकों के पास एआई प्रणालियों के प्रशिक्षण में अपने कार्यों को सीमित करने रखने का विकल्प नहीं होगा। इसमें कहा गया, '' कॉपीराइट स्वामियों के रॉयल्टी प्राप्त करने के अधिकार को संरक्षित करके तथा अधिकार धारकों द्वारा बनाए गए तथा सरकार द्वारा नामित एकल संगठन के माध्यम से इसे प्रशासित करके...मॉडल का उद्देश्य एआई प्रशिक्षण के वास्ते एआई डेवलपर के लिए सामग्री तक आसान पहुंच प्रदान करना, लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाना, लेनदेन लागत को कम करना तथा अधिकार धारकों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना है।'' पत्र में कहा गया है कि यह हाइब्रिड मॉडल एआई डेवलपर को एआई प्रशिक्षण के लिए कॉपीराइट कार्यों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एकल खिड़की भी प्रदान करता है।

इसमें कहा गया कि जनरेटिव एआई में दुनिया को बेहतर बनाने की अपार क्षमता है जो इसके विकास का समर्थन करने वाले नियामक माहौल की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हालांकि, जिन प्रक्रियाओं के द्वारा एआई प्रणालियों को प्रशिक्षित किया जाता है जिनमें अक्सर कॉपीराइट धारकों से अनुमति लिए बिना कॉपीराइट सामग्री का उपयोग किया जाता है तथा उनके द्वारा उत्पन्न सामग्री (आउटपुट) की प्रकृति ने कॉपीराइट कानून के इर्द-गिर्द एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। पत्र में कहा गया कि कि मुख्य चुनौती यह है कि प्रौद्योगिकी प्रगति को बाधित किए बिना, मानव निर्मित कार्यों में कॉपीराइट की सुरक्षा कैसे की जाए। इसमें कहा गया, '' इस समस्या के समाधान के लिए, देश में रचनात्मक परिवेश की अखंडता को बनाए रखने और साथ ही एआई नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक संतुलित नियामक ढांचे की आवश्यकता है।'' इसके अलावा समिति ने स्वीकार किया कि बड़ी मात्रा में डेटा एवं उच्च गुणवत्ता वाले डेटा तक पहुंच एआई विकास के लिए महत्वपूर्ण है। लंबी बातचीत और उच्च लेनदेन लागत नवाचार को रोक सकती है, विशेष रूप से स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम को...।

इसमें कहा गया कि समिति ने एक हाइब्रिड दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है जो एआई प्रशिक्षण के लिए सभी कानूनी रूप से हासिल की गई कॉपीराइट सामग्री की उपलब्धता को अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है, व्यक्तिगत बातचीत की आवश्यकता के बिना, डेवलपर के लिए लेनदेन लागत कम हो जाती है और उनके लिए अनुपालन बोझ कम हो जाता है। समिति ने कॉपीराइट धारकों को उचित मुआवजा देने, रॉयल्टी दरों पर न्यायिक समीक्षा स्थापित करने, अधिकार धारकों को भुगतान की आसान एवं सीधी प्रक्रिया तथा स्टार्टअप एवं छोटी कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है।

ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में 5 वर्ष में 75 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करेंगे: गौतम अदाणी

धनबाद। अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने मंगलवार को कहा कि उनका समूह अगले पांच साल में ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में 75 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करेगा। धनबाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइंस) के 100वें स्थापना दिवस समारोह में अदाणी ने कहा कि समूह गुजरात के खावड़ा में 520 वर्ग किलोमीटर में फैला दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बना रहा है।

उन्होंने कहा, ''2030 तक अपनी पूरी क्षमता पर, यह पार्क 30 गीगावाट हरित ऊर्जा उत्पन्न करेगा। औसत घरेलू खपत के हिसाब से यह ऊर्जा प्रति वर्ष छह करोड़ से अधिक मकानों को बिजली मुहैया कराने के बराबर है।'' अदाणी ने कहा, ''10 गीगावाट की स्थापना पहले ही हो चुकी है। हम दुनिया में सबसे कम लागत वाली हरित 'इलेक्ट्रॉन' उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जो ऊर्जा परिवर्तन में एक वैश्विक मानक स्थापित करेगा।'' उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता है, लेकिन इसकी प्रति व्यक्ति खपत ''प्रति वर्ष 1,400 किलोवाट घंटे से भी कम है जो वैश्विक औसत के आधे से भी कम तथा अमेरिका के 10वें हिस्से और यूरोप के पांचवें हिस्से के बराबर है।''

वैश्विक स्थिरता बहस का उल्लेख करते हुए अदाणी ने कहा, ''यह विमर्श 2025 सीओपी-30 में सामने आई, जहां एक रिपोर्ट में भारत की स्थिरता 'रैंकिंग' को यह तर्क देते हुए घटा दिया गया कि हमारे देश में कोयला निकालने की समयसीमा का अभाव है और कोयला ब्लॉक की नीलामी जारी है।'' उन्होंने कहा कि हां, कुल कार्बन उत्सर्जन के मामले में हम तीसरे स्थान पर हैं लेकिन प्रति व्यक्ति हमारे लोग दो टन से कम उत्सर्जन करते हैं जबकि अमेरिका में यह 14 टन, चीन में नौ टन और यूरोप में छह टन है। अदाणी ने कहा कि 200 वर्ष की औद्योगिक गतिविधि में संचयी वैश्विक उत्सर्जन की बात करें तो हमारा देश केवल चार प्रतिशत उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। वहीं यूरोप 13 प्रतिशत, अमेरिका 19 प्रतिशत और चीन 20 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है।

आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की नयी ऋण सहायता मंजूर की

इस्लामाबाद। आईएमएफ ने द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत पाकिस्तान को करीब 1.2 अरब डॉलर की नयी ऋण सहायता को मंजूरी दे दी है। इस ऋण सहायता से स्पष्ट होता है कि विनाशकारी बाढ़ के बावजूद देश ने स्थिरता बनाए रखी है।

समाचार पत्र 'डॉन' ने मंगलवार को एक खबर में बताया कि आईएमएफ कार्यकारी निदेशक मंडल ने सोमवार को वाशिंगटन में आयोजित बैठक में दोहरे 'ट्रैक बेलआउट', 37 महीने की विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) एवं जलवायु-केंद्रित टिकाऊ स्थिरता सुविधा (आरएसएफ) के तहत यह मंजूरी दी। नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान वर्तमान में आईएमएफ के 24वें कार्यक्रम में है। इसके तहत पिछले साल उसे 39 महीनों की अवधि में सात अरब डॉलर की सहायता प्रदान करने पर सहमति बनी थी। खबर में कहा गया कि नवीनतम अनुमोदन के तहत पाकिस्तान को ईएफएफ के तहत एक अरब डॉलर और आरएसएफ के तहत 20 करोड़ डॉलर की सहायता राशि निकालने की अनुमति है।

आईएमएफ के उप प्रबंध निदेशक एवं कार्यवाहक प्रमुख निगेल क्लार्क ने बयान में कहा, '' अनिश्चित वैश्विक माहौल को देखते हुए, पाकिस्तान को व्यापक आर्थिक स्थिरता को और मजबूत करने के लिए विवेकपूर्ण नीतियों को बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही मजबूत, निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाली एवं टिकाऊ मध्यम अवधि की वृद्धि हासिल करने के लिए आवश्यक सुधारों में तेजी लाने की जरूरत है।''

उन्होंने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि असली परीक्षा इन प्रतिबद्धताओं को ठोस आर्थिक सुधार में बदलने की होगी। आईएमएफ ने पाकिस्तान के कमजोर वित्तीय प्रबंधन, नकदी निगरानी एवं सार्वजनिक संसाधन आवंटन के लिए जवाबदेही पर पिछले महीने असंतोष व्यक्त किया था और करदाताओं के पैसे के व्यक्तिगत एवं राजनीतिक दुरुपयोग को कम करने की सलाह दी थी।

डीजीसीए ने इंडिगो की उड़ान सेवाओं में की 5 प्रतिशत की कटौती

मुंबई। विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने मंगलवार को कहा कि उसने एक दिसंबर 2025 से बड़े पैमाने पर उड़ान व्यवधानों के बाद विमान कंपनी इंडिगो की उड़ान सेवाओं में पांच प्रतिशत की कटौती है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस संबंध में मंगलवार को एक आदेश जारी किया। बयान के अनुसार, सभी क्षेत्रों में उड़ानों में कटौती की गई है खासकर उच्च मांग वाले मार्गों पर। इंडिगो को बुधवार शाम पांच बजे तक डीजीसीए को संशोधित कार्यक्रम (शेड्यूल) प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है। इससे पहले नगर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने सोमवार को कहा था कि सरकार चालू शीतकालीन कार्यक्रम के तहत इंडिगो द्वारा जिन मार्गों पर उड़ान सेवाएं संचालित की जाती हैं उन्हें कम किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के शीतकालीन कार्यक्रम के तहत विमानन कंपनी प्रतिदिन 2,200 से अधिक उड़ानें संचालित कर रही हैं।

भारत और स्वीडन ने इस्पात एवं सीमेंट क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए मिलाया हाथ

नई दिल्ली। टाटा स्टील जैसी अग्रणी भारतीय कंपनियों ने घरेलू इस्पात एवं सीमेंट क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए सात परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वीडिश प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तकों के साथ हाथ मिलाया है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जैसे-जैसे भारत 2070 तक अपने शुद्ध-शून्य लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, देश के बुनियादी ढांचे के विकास, औद्योगिक विकास एवं दीर्घकालिक जलवायु महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देने के लिए इन कठिन क्षेत्रों से उत्सर्जन को कम करना आवश्यक होगा। इन परियोजनाओं में इस्पात निर्माण के लिए रोटरी भट्टों में हाइड्रोजन का उपयोग, हरित सीमेंट के उत्पादन के लिए 'स्टील स्लैग' का पुनर्चक्रण तथा सीमेंट के कार्बन मुक्त होने में सहायता के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) का उपयोग शामिल है। इसमें कहा गया कि प्रमुख आईटी उद्योग परिवर्तन साझेदारी के तहत भारत में 'प्री-पायलट' (शुरुआती परीक्षण) व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए सात नवीन परियोजनाओं का चयन किया गया है।

इन्हें भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और स्वीडिश ऊर्जा एजेंसी से वित्त पोषण प्राप्त होगा। अग्रणी भारतीय एवं वैश्विक कंपनियां, अनुसंधान संस्थान तथा प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तक भारत के इस्पात एवं सीमेंट क्षेत्रों के लिए इन सात कार्बन मुक्त (डीकार्बोनाइजेशन) परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रमुख प्रतिभागियों में टाटा स्टील, जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, जिंदल स्टील, प्रिज्म जॉनसन, सेमविजन के साथ-साथ स्वीडिश प्रौद्योगिकी अग्रणी कंथल तथा स्वेरिम शामिल हैं।

बयान में कहा गया कि भारत के शीर्ष संस्थान आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी-आईएसएम धनबाद, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी हैदराबाद और दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन सात परियोजनाओं में भागीदार हैं।

'वी शांताराम' में तमन्ना भाटिया की पहली झलक ने बढ़ाई उत्सुकता

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी इन दिनों अपनी नई फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं, जो भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्मकार 'वी. शांताराम' की जिंदगी पर आधारित बायोपिक है। हाल ही में सिद्धांत की धोती-कुर्ता लुक वाली पहली झलक सामने आई थी, जिसके बाद अब फिल्म से अभिनेत्री तमन्ना भाटिया का फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया गया है। यह बायोपिक अभिजीत शिरीष देशपांडे द्वारा निर्देशित की जा रही है। वैरायटी की रिपोर्ट के अनुसार तमन्ना भाटिया इस बायोपिक में जयश्री की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म से जारी उनके पहले पोस्टर में वह गुलाबी नौवारी साड़ी पहने नजर आती हैं, जो एकदम भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर की याद दिलाता है। तमन्ना का यह पारंपरिक लुक बेहद खूबसूरत, सौम्य और प्रभावशाली दिखाई दे रहा है। फैंस अब उनके इस नए अवतार को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्सुक हैं। जयश्री, वी. शांताराम की दूसरी पत्नी थीं और हिंदी सिनेमा की एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती हैं। उन्होंने डॉ. कोटनीस की अमर कहानी, दहेज, शकुंतला, चंद्र राव मोरे जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से खास पहचान बनाई। शांताराम के फिल्मी सफर में जयश्री की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है, और बायोपिक में उनकी मौजूदगी कहानी की भावनात्मक और रचनात्मक गहराई को और बढ़ाती है। फिल्म की कहानी और पटकथा दोनों का लेखन भी अभिजीत शिरीष देशपांडे ने ही किया है। हालांकि इसकी रिलीज डेट अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन सिद्धांत और तमन्ना के लुक्स ने फिल्म के प्रति उत्सुकता को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है।

केदारनाथ को रचना मेरे लिए अपने-आप में एक भावनात्मक तीर्थयात्रा थी : कनिका ढिल्लन

मुंबई। बॉलीवुड की जानीमानी लेखिका कनिका ढिल्लन का कहना है कि फिल्म केदारनाथ को रचना उनके लिए अपने-आप में एक भावनात्मक तीर्थयात्रा थी। फिल्म केदारनाथ ने अपनी रिलीज़ के सात साल पूरे कर लिये हैं।एक ऐसी फिल्म जिसने अपनी मार्मिक प्रेमकहानी को 2013 उत्तराखंड की विनाशकारी बाढ़ की वास्तविक त्रासदी के साथ संवेदनशीलता से जोड़कर प्रस्तुत किया। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की यह फिल्म न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से महत्वाकांक्षी थी, बल्कि भावनात्मक रूप से भी दर्शकों को बेहद छूने वाली रही। यही वह फिल्म थी जिसने सारा अली खान को बॉलीवुड में एक यादगार लॉन्च दिया और उनके नाम सर्वश्रेष्ठ डेब्यू (महिला) का फिल्मफेयर अवॉर्ड दर्ज हुआ। अभिषेक कपूर के निर्देशन में बनी केदारनाथ को समीक्षकों और दर्शकों,दोनों का भरपूर प्यार मिला। लेकिन फिल्म की सबसे मजबूत नींव थी इसका गहन और संवेदनशील लेखन, जिसे रचा था कनिका ढिल्लन ने। कनिका ढिल्लन की कहानी ने इस आपदा को सिर्फ एक विशाल प्राकृतिक घटना की तरह नहीं दिखाया, बल्कि इसे मानवीय संवेदना और प्रेम के साथ जोड़कर एक भावपूर्ण कथा में बदल दिया। फिल्म की आत्मा मांडाकिनी 'मुख्कू' (एक पुजारी की बेटी) और मंसूर खान (एक मुस्लिम पिट्ठू) की प्रेमकहानी में बसती है। एक ऐसा अंतरधार्मिक रिश्ता जो समाज की जड़बद्ध मान्यताओं को चुनौती देता है। ढिल्लन ने इस प्रेम को उस विनाशकारी बाढ़ की पृष्ठभूमि में रखा, जहाँ प्रकृति की शक्ति इंसानी विभाजनों से कहीं बड़ी साबित होती है। उनका लेखन इस बात का उदाहरण है कि किस तरह एक प्राकृतिक आपदा के बीच भी इंसानी भावनाएँ, विश्वास और त्याग की कथा में चमक सकती है। 7वीं वर्षगांठ के मौके पर अपनी भावनाएँ साझा करते हुए कहा कि केदारनाथ को रचना मेरे लिए अपने-आप में एक भावनात्मक तीर्थयात्रा थी। यह उस निर्मल प्रेम को पकड़ने की कोशिश थी जो एक भयावह त्रासदी के बीच भी चमकता है। सात साल बाद भी मंसूर और मुख्कू की कहानी को इतना प्यार मिलता देखना बेहद भावुक कर देने वाला है। यह याद दिलाता है कि सशक्त कहानियाँ हमेशा अपना रास्ता बना ही लेती हैं।

शकुन बत्रा के साथ अपना अगला प्रोजेक्ट करेंगे अली फज़ल!

मुंबई। बॉलीवुड के जानेमाने अभिनेता अली फज़ल, निर्देशक शकुन बत्रा के साथ अपना अगला प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अली फज़ल,इस समय मिर्जापूरः द मूवी और आमिर ख़ान की आने वाली फ़िल्म लाहौर 1947 की शूटिंग में व्यस्त हैं। वह अब एक नए प्रोजेक्ट को लेकर सुर्खियों में हैं। चर्चा है कि अली फजल जल्द ही शकुन बत्रा के साथ एक नया काम करने वाले हैं। हाल ही में अली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सिर्फ इतना लिखा – "इट्स ए रैप"। इस छोटे से मैसेज ने लोगों के बीच जिज्ञासा बढ़ा दी है कि शायद अली ने चुपचाप कोई नया प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है।

भारत को अमेरिकी बाजारों में सस्ते दामों पर चावल नहीं बेचना चाहिए : डोनाल्ड ट्रंप

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत को अमेरिकी बाजार में चावल 'डंप' करना (सस्ते दामों पर बेचना) नहीं चाहिए और वह इस मामले से 'निपट लेंगे।' ट्रंप ने चेतावनी दी कि शुल्क (टैरिफ) लगाकर इस 'समस्या' का आसानी से हल निकल जाएगा।

ट्रंप ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय 'व्हाइट हाउस' में खेती और कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों तथा अपने कैबिनेट के प्रमुख सदस्यों खासकर वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और कृषि मंत्री ब्रूक रोलिन्स के साथ एक गोलमेज बैठक की। उन्होंने किसानों के लिए 12 अरब डॉलर की संघीय सहायता की घोषणा की। लुइसियाना में अपने परिवार के कृषि कारोबार 'केनेडी राइस मिल' का संचालन करने वाली मेरिल केनेडी ने ट्रंप से कहा कि देश के दक्षिणी

हिस्से में चावल उत्पादक 'वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं' और अन्य देश अमेरिकी बाजार में चावल 'डंप' कर रहे हैं यानी कि बेहद सस्ते दामों पर चावल बेच रहे हैं। जब ट्रंप ने पूछा कि कौन से देश अमेरिका में चावल सस्ते दामों पर बेच रहे हैं तो राष्ट्रपति के बगल में बैठीं केनेडी ने जवाब दिया कि भारत और थाईलैंड, यहां तक कि चीन भी प्यूर्टो रिको में चावल सस्ते दामों पर बेच रहा है। प्यूर्टो रिको कभी अमेरिकी चावल का सबसे बड़ा बाजार हुआ करता था।

हमने कई वर्षों से प्यूर्टो रिको में चावल नहीं भेजे हैं। केनेडी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए शुल्क काम कर रहे हैं लेकिन हमें इसे और बढ़ाने की जरूरत है। ट्रंप ने फिर बेसेंट की ओर देखते हुए कहा कि भारत, मुझे भारत के बारे में बताइए। भारत को ऐसा करने की अनुमति क्यों है? उन्हें शुल्क देना होगा। क्या उन्हें चावल पर छूट मिली हुई है? इस पर बेसेंट ने कहा कि नहीं सर, हम अभी उनके साथ व्यापार सौदे पर बातचीत कर रहे हैं। केनेडी ने ट्रंप को यह भी बताया कि भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में एक मामला चल रहा है। ट्रंप ने कहा कि इसे 'बहुत आसानी से निपटाया जा सकता है।' उन्होंने कहा कि यह उन देशों पर शुल्क लगाकर बहुत जल्दी हल हो जाएगा, जो अवैध रूप से सामान भेज रहे हैं। आपकी समस्या एक दिन में हल हो जाएगी इसलिए हमें उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीतना है। 'इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स फेडरेशन' के आंकड़ों के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है और वैश्विक बाजार में 28 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। वह शीर्ष निर्यातक भी है, जिसकी 2024-25 में वैश्विक निर्यात में 30.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

भारत चावल की जो किस्में वैश्विक स्तर पर निर्यात करता है, उनमें 'सोना मसूरी' अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में पसंद की जाती है। ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। इसमें रूस से तेल खरीद पर 25 प्रतिशत शुल्क भी शामिल है।

हम 'क्वाड' के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है: मंत्री रुबियो

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका 'क्वाड' के प्रति 'पूरी तरह प्रतिबद्ध' है तथा आने वाले वर्षों में इस समूह को और मजबूत करेगा। 'क्वाड' (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है। रुबियो ने सोमवार को कहा कि हम क्वाड के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आने वाले समय में जापान और भारत के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाने के लिए और काम करेंगे।

ऑस्ट्रेलिया–अमेरिका मंत्रिस्तरीय वार्ताओं से पहले उन्होंने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स तथा ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग की मौजूदगी में विदेश मंत्रालय में संयुक्त बयान देते हुए यह बात कही। रुबियो के अनुसार, इस साल जनवरी में विदेश मंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक उनकी पहली आधिकारिक बैठक थी। उन्होंने कहा कि मेरे नाम पर मुहर लगी, मैंने नीचे शपथ ली और सीधे इसी लिफ्ट से ऊपर आकर इस कमरे में पहुंचा। विदेश मंत्री के रूप में मेरा पहला कार्यक्रम यहीं इसी कमरे में क्वाड के साथ हुआ था। रुबियो

ने कहा कि जहां तक मुझे याद है, इस साल हमारी कम से कम तीन बैठकें हुई हैं। हम आने वाले साल में इस सहयोग को और आगे बढ़ाएंगे तथा ऐसी और बैठकों की उम्मीद करते हैं।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया, रुबियो और वोंग ने 21 जनवरी को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए मुलाकात की थी। यह बैठक 'व्हाइट हाउस' में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद समूह की पहली बैठक थी। क्वाड विदेश मंत्रियों की जुलाई में वाशिंगटन में फिर से मुलाकात हुई थी।

जकार्ता में कार्यालय भवन में आग लगने से कम से कम 20 लोगों की मौत

जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मंगलवार को आग लगने की एक भयावह घटना सामने आई है, जिसने पूरे शहर को दहला दिया। सेंट्रल जकार्ता में एक सात मंजिला कार्यालय की इमारत में भीषण आग लग गई, जिसके चलते अब तक 20 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आग की लपटों और धुएँ ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे आसमान में घना काला धुआँ फैल गया और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई।

सेंट्रल जकार्ता के पुलिस प्रमुख सुसात्यो पुरनोमो कोंड्रो ने मरने वालों की संख्या की पुष्टि की है। उन्होंने बताया, अब तक 20 शव निकाले गए हैं, जिनमें 5 पुरुष और 15 महिलाएं शामिल हैं। दुखद रूप से, मरने वालों में एक गर्भवती महिला भी शामिल थी।

अधिकारियों ने बताया कि यह इमारत टेरा ड्रोन इंडोनेशिया के दफ्तर थे, जो खनन से लेकर कृषि तक के क्षेत्रों के लिए ड्रोन सेवाएँ प्रदान करती है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी और फिर तेजी से ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। आग लगने के समय कुछ कर्मचारी लंच कर रहे थे, जबकि कई लोग बाहर थे। एक चैनल पर दिखाए गए फुटेज में दमकलकर्मी पोर्टेबल सीढ़ियों का उपयोग करके ऊपरी मंजिलों से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे। फिलहाल, आग पर काबू पा लिया गया है, और अधिकारियों का ध्यान अभी भी लोगों को निकालने और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है।

नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी सहित वैश्विक नेताओं से मजबूत संबंधों का उल्लेख किया

यरुशलम। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को संसद में दिए एक तेज तर्रार भाषण में देश के प्रबंधन को लेकर अपनी नीति का बचाव करते हुए कहा कि इस यहूदी राष्ट्र के खिलाफ बढ़ती यहूदी-विरोधी भावनाओं के बावजूद इजराइल को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत दुनिया के कई देशों एवं नेताओं का अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त है।

नेतन्याहू ने संसद में तथाकथित '40 हस्ताक्षर बहस' के दौरान यह बात कही। यह बहस ऐसा संसदीय तंत्र है जिसके तहत विपक्ष प्रधानमंत्री को महीने में एक बार इजराइली संसद 'क्नेसेट' के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। इस दौरान नेतन्याहू ने अपनी सरकार की नीतियों,

खासकर इजराइल के विदेश संबंधों का जोरदार तरीके से बचाव किया। उन्होंने कहा कि आज इजराइल पहले से कहीं अधिक मजबूत है। विपक्ष द्वारा लगाए गए इस आरोप का जवाब देते हुए कि 'इजराइल की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी है', नेतन्याहू ने तर्क दिया कि हमास के साथ दो वर्षों से युद्ध जारी होने के बावजूद इजराइल कूटनीतिक, सैन्य और आर्थिक स्तर पर अब भी मजबूत है। उन्होंने वैश्विक नेताओं के साथ अपने संबंधों को रेखांकित किया। नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया भर के अनेक देश और बहुत से विश्व नेता हमसे जुड़ना चाहते हैं।

हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि चुनौतियां भी हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों में बढ़ती 'यहूदी-विरोधी भावनाओं' के लिए दो कारण बताए : लगभग हर देश में, खासकर यूरोप में पहुंचे कट्टरपंथी मुस्लिम अल्पसंख्यक और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही यहूदी-विरोधी उकसावे वाली सामग्री। उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर में इस यहूदी-विरोध का मुकाबला कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इसके बावजूद इजराइल की कूटनीतिक स्थिति अब भी मजबूत है।

उन्होंने इस सप्ताह जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की यात्रा को इसका उदाहरण बताया और कहा कि यह यात्रा मर्ज की स्वयं की पहल पर हो रही है। उन्होंने कहा कि और भी कई महाशक्तियां हमारे साथ आ रही हैं: मैं अपने पुराने मित्र भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अक्सर बात करता हूं। हमने जल्द ही मिलने की योजना बनाई है और मुझे आपको बताना चाहिए कि डेढ़ अरब की आबादी वाला विशाल देश भारत हमारे साथ संबंध और मजबूत करना चाहता है।

नेतन्याहू ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जर्मनी, भारत हमारे साथ हैं और आपके तथाकथित राजनीतिक पतन का एक और संकेत यह है कि महीने के अंत में मैं अपने मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक और मुलाकात के लिए अमेरिका जाऊंगा।